राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

# क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शुक्रवार 13 मार्च 2026 वर्ष-9,अंक-47 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## चंडीगढ़ पुलिस की आतंकी पन्नू के खिलाफ अनट्रेस्ड रिपोर्ट

● जजों को मारने की दी थी धमकी, नहीं मिला सुराग

**चंडीगढ़ (एजेंसी)।** चंडीगढ़ पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी और प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज चार साल पुराने मामले में अनट्रेस्ड रिपोर्ट दाखिल कर दी है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पुलिस की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सुसाइड बॉम्बर के जरिए जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा था। इस संबंध में वर्ष 2022 में चंडीगढ़ के सेक्टर-3 पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 506 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के अनुसार, यह एफआईआर सेक्टर-3 थाने के तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया था कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट मिली थी, जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू और ह्यकुबार्नी जत्थाह्न की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक-एक जज को सुसाइड बॉम्बर के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी।

## दिल्ली सरकार ने कहा: पेट्रोल-गैस की कोई कमी नहीं

● घबराहट में खरीदारी करने से बचें उपभोक्ता

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** देश की राजधानी दिल्ली में भी गैस की कमी से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। गैस एजेंसियों के सामने लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में गैस के उपयोग को सीमित कर स्थिति से निपटने की कोशिश की जा रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने लोगों से घबराहट में अधिक खरीदारी (पैनिक बाइंग) करने से बचने की सलाह दी है। गुरुवार शाम दिल्ली सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि शहर में पेट्रोल या गैस की कोई कमी नहीं है। प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपभोक्ताओं और सीएनजी चालित वाहनों को गैस उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और घबराहट में गैस-पेट्रोल की अधिक खरीदारी करने से बचने की अपील की है। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड प्रमुख एजेंसी है जो उपभोक्ताओं को घरेलू और वाहनों के उपयोग के लिए गैस उपलब्ध कराती है।

## चुनावी ड्यूटी पर सीआरपीएफ जवान बेहाल...

### खुले में हथियार घर, पानी की किल्लत, कमांडेंट को लेना पड़ा होटल

**गुवाहाटी (एजेंसी)।** देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' की दो कंपनियों के जवान, जिन्हें असम के जोरहाट में चुनावी ड्यूटी के लिए भेजा गया था, बेहाल हो गए हैं। वजह, वहां पर जवानों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं। पीने और नहाने के पानी की किल्लत है। यहां तक कि हथियार रखने के लिए स्ट्रॉग रूम 'कोत' जैसी कोई व्यवस्था तक नहीं है। अस्थायी तौर पर बाथरूम का निर्माण, पन्नी की मदद से किया गया है। एडहॉक कमांडेंट को पिछले एक माह से होटल में ठहरना पड़ रहा है।

सीआरपीएफ के एडहॉक कमांडेंट ने आधी अधूरी व्यवस्थाओं की शिकायत 11 मार्च को महानिरीक्षक पूर्वोत्तर सेक्टर (स्टेट फोर्स कॉर्डिनेटर), महानिरीक्षक जोरहाट, उप महानिरीक्षक (परिचालन) और महानिदेशालय रेंज, खटखटी को दी है। शिकायत की प्रति अमर उजाला डॉट कॉम के पास मौजूद है। सीआरपीएफ की एडहॉक 331 बटालियन की दो कंपनियां 'डी 216', 'ई 216' एवं 'डेट 331' (डिटेचमेंट टुकड़ी, जिसे छोटा हेडक्वार्टर भी कहा जाता है), को मरयानी रेलवे स्टेशन की जमीन पर ठहराया गया है। यहां पर जो हाल बना है, वह रेलवे का वर्कशॉप है। इस हॉल में पंखे तक नहीं लगे हैं। लाइट की उचित सुविधा नहीं है। मोबाइल चार्ज करने की व्यवस्था भी नहीं है। सीआरपीएफ की दोनों कंपनियों के कोत 'हथियार रखने वाली जगह' के लिए कोई भी कमरा मुहैया नहीं कराया गया। इसके चलते हथियारों की सुरक्षा के संबंध में जारी अनुदेशों की पूर्ण अनुपालना संभव नहीं हो रही। पन्नी से बने बाथरूमों में पानी, दरवाजे व लाइट की सुविधा नहीं है। कुल 20 टॉयलेट बनाए गए हैं, जिनमें 10 इंडियन व 10 वेस्टर्न टॉयलेट हैं। इनमें फ्लश तक उपलब्ध नहीं है। जवानों को पीने का पानी 'जार' के हिसाब से मुहैया करा जा रहा है।

#### कमांडेंट को इसलिए लेना पड़ा होटल

**चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, जवानों को रहने के लिए सुरक्षित एवं बुनियादी सुविधाओं से लैस जगह मिलनी चाहिए, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। एडहॉक कमांडेंट को जो आवास दिया गया, उसमें न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं मिली। कंबल, चद्दर, बाल्टी, मग, बेड और टेबल कुर्सी आदि तक नहीं है। रैंक के अनुरुप एडहॉक कमांडेंट को जो सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए थीं, वे प्रदान नहीं की गई। नतीजा, एडहॉक कमांडेंट को 10 फरवरी से 11 मार्च तक स्वयं के खर्च पर एक होटल में ठहरना पड़ा। 'डेट' के कार्यालय एवं अधिकारियों के दफ्तर के लिए कोई रूम उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि अग्रिम व्यवस्था और लोकल प्रशासन के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी 'डेट' की होती है।**

## सरकार ने माना: घबराहट की वजह से सिलेंडर बुकिंग बढ़ी

### रोज 50 लाख सिलेंडर डिलीवर हो रहे, 1 लाख पेट्रोल पंप पर तेल की कमी नहीं

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारत सरकार के विदेश, शिपिंग, पेट्रोलियम, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कच्चे तेल और गैस की किल्लत को लेकर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरकार ने माना कि देश में हालात चुनौतीपूर्ण हैं और घबराहट के कारण देशभर में सिलेंडर बुकिंग में कई गुना बढ़ोतरी देखी गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि भारत अपनी जरूरत का करीब 60% LPG आयात करता है, जिसमें से लगभग 90% सप्लाई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आती है। देश में रोजाना करीब 50 लाख LPG सिलेंडर की डिलीवरी की जाती है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश में कच्चे तेल की सप्लाई की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक है और देश के करीब एक लाख पेट्रोल पंपों में से किसी पर भी ईंधन खत्म होने (ड्राई-आउट) की स्थिति नहीं है। अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग के बीच भारत में LPG की डिमांड बढ़ गई है। देशभर में गैस सिलेंडर एजेंसियों के बार लम्बी लाइनें लग रही हैं। सिलेंडरों की कालाबाजारी भी होने लगी है। राज्यों में 900 रुपये के घरेलू गैस सिलेंडर के लिए ₹1800 तक वसूले जा रहे हैं। देश में पेट्रोल-डीजल और LPG की उपलब्धता को लेकर स्थिति काफी सहज और संतोषजनक है। भारत रोजाना करीब 55 लाख बैरल कच्चे तेल का इस्तेमाल करता है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर होने के कारण पेट्रोल-डीजल जैसे उत्पादों की उपलब्धता को लेकर भरोसा बना हुआ है। 9 मार्च को पेट्रोलियम मंत्रालय ने Essential Commodities Act के तहत सभी रिफाइनरियों को LPG उत्पादन अधिकतम करने का आदेश दिया था। इसके बाद घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है और अब यह 25% से बढ़कर 28% हो गया है। भारत सरकार हर तिमाही राज्यों को केरोसिन आवंटित करती है। हर तीन महीने में लगभग 1 लाख किलोलीटर केरोसिन राज्यों को दिया जाता है। आज जारी किए गए नए आदेश के तहत राज्य सरकारों को अतिरिक्त 48 हजार किलोलीटर केरोसिन और जारी किया जाएगा।

#### होर्मुज स्ट्रेट का लगभग बंद होना

**भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का बंद होना है। ये करीब 167 किमी लंबा जलमार्ग है, जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा है। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा।\ दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक और कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर हैं। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है।**

## अय्यर के लेटर का शशि थरूर ने दिया जवाब

■ कहा: मेरी देशभक्ति पर सवाल उठाना गलत

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं शशि थरूर और मणि शंकर अय्यर के बीच तनाव और बढ़ गया है। थरूर ने गुरुवार को अय्यर के ओपन लेटर का जवाब ओपन लेटर से दिया है। थरूर ने कहा है कि विदेश नीति पर मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे किसी की नीयत या देशभक्ति पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। मणि शंकर अय्यर ने 10 मार्च को अपने लेटर में विदेश नीति पर थरूर के रुख की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि थरूर ने अमेरिका-इजराइल और ईरान से जुड़े मुद्दों पर भारत के नैतिक रुख को कमजोर किया है। उन्होंने कहा कि भारत को शक्तिशाली देशों के दबाव में चुप नहीं रहना चाहिए और गांधी-नेहरू की नैतिक राजनीति से प्रेरणा लेनी चाहिए। अय्यर ने लेटर में थरूर से पूछा- क्या आप सचमुच नरेंद्र मोदी की कृपा पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे आपको वह लाभ दे सकते हैं जो विपक्ष आपको नहीं दे सकता? थरूर ने जवाब में कहा- मैंने अब तक सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन अब जवाब देना जरूरी हो गया था। अय्यर ने लेटर के जरिए भारत के विदेश नीति पर थरूर के पक्ष की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा- ऐसा लगता है कि आपने रूस और चीन जैसे दो बड़े शक्तिशाली देशों के बारे में भी नहीं सुना, जो ईरान के लोगों पर हो रहे हमले की क्रूरता, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन और ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या जैसी बर्बर घटनाओं पर खुलकर बोल रहे हैं—जैसा नेहरू के दौर में भारत करता था और करता।

## फारूक अब्दुल्ला बोले: ऊपर वाले ने बचाया

● हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी

**श्रीनगर (एजेंसी)।** नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। हमलावर ने सिर पर कुछ इंच दूर से गोली चलाई थी। गनीमत रही कि सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर का हाथ ऊपर कर दिया और उन्हें गोली नहीं लगी। अधिकारियों के मुताबिक फारूक जम्मू में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी थे। फारूक अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा- मुझे ऊपर वाले ने बचाया है। शादी से निकलते समय मैंने कुछ आवाज सुनी, मुझे लगा कि यह

पटाखा है। बाद में मुझे बताया गया कि एक आदमी ने पिस्तौल से दो गोलियां चलाईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच-बचाव किया, जिससे हथियार ऊपर की ओर हो गया और नुकसान होने से बच गया। वहीं, हमलावर कमल ने पुलिस को बताया कि वह पिछले 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। हमलावर को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में फायरिंग की घटना के बाद फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बात की और उनका हालचाल पूछा। मेरे पास मेरी सिक्योरिटी की तारीफ करने के लिए शब्द नहीं हैं। लोकल पुलिस वाले, मेरे साथ रहने वाले सिक्योरिटी वाले और NSG के सदस्य शामिल थे, जो मेरी सुरक्षा के लिए मेरे सामने खड़े थे। मैं उस आदमी को नहीं जानता, न ही किसी ने मुझे उसके बारे में कभी कुछ बताया। जहां तक उसके मकसद की बात है मुझे कैसे पता चलता कि वह क्या हो सकता था? सवाल यह है कि इस शादी में कई जाने-माने लोग मौजूद थे, इसलिए पुलिस को सही सावधानी बरतनी चाहिए थी।

## यूपी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम के 2 अफसरों की हत्या

**बदायूं।** यूपी के बदायूं में ठेकेदार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के DGM यानी उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता (55 साल) और असिस्टेंट मैनेजर सेल्स हर्षित मिश्रा (35 साल) की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी अजय प्रताप सिंह उर्फ रामू प्लांट में पराली वेंडर था।

तीन महीने पहले उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था। इससे वह खुन्नस मान रहा था। उसने जान से मारने की धमकी दी थी। हर्षित मिश्रा ने 4 फरवरी को अजय के खिलाफ मूसाझाग थाने में केस दर्ज कराया था। सिक्योरिटी मांगी थी। सुधीर गुप्ता अजय की धमकियों से इस कदर खौफ में थे कि उन्होंने वीआरएस ले लिया था। 31 मार्च को उन्हें चार्ज छोड़ना था। बावजूद इसके आरोपी पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया।अजय गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे बोलेरो से प्लांट पर पहुंचा। बोलेरो में अजय समेत 6 लोग बैठे थे। इनमें प्लांट के 4 कर्मचारी और ड्राइवर था। कर्मचारियों की 2 बजे से शिफ्ट थी। प्लांट में एंट्री के समय बोलेरो चेक नहीं की गई। अजय ऑटोमैटिक गन लेकर पहुंचा था। उसने सुधीर और हर्षित पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे दोनों की मौत हो गई।

## ईरानी सुप्रीम लीडर बोले: अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे

### पद संभालने के बाद मुजतबा का पहला बयान, कहा- होर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा

**तेल अवीव/तेहरान (एजेंसी)। नई दिल्ली (एजेंसी)।** ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद गुरुवार को अपना पहला बयान जारी किया। इसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि वह मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को बंद कर दे, नहीं तो उन पर हमले जारी रहेंगे। मुजतबा ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है कि उन्हें ईरान पर किए गए हमलों की ह्यभरपाईह्ल करनी होगी। ईरान के सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाए गए संदेश में खामेनेई ने कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता भी नहीं खोला जाएगा। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध लगातार तेज हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल के हमलों के पहले दिन मोजतबा खामेनेई के पैर में फ्रैक्चर हो गया था और उन्हें हल्की चोटें भी आई थीं। बताया गया कि वह उसी हवाई हमले में घायल हुए थे, जिसमें उनके पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। मिडिल-ईस्ट में जारी इस संघर्ष के बीच भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों ने पिछले कुछ दिनों में तीन बार बातचीत की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उनसे पूछा गया कि क्या ईरान ने भारत जाने वाले जहाजों को अनुमति दी है। इस पर उन्होंने कहा कि फिलहाल इस विषय पर ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हाल की बातचीत में समुद्री शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जायसवाल ने यह भी कहा कि भारत ने ईरान के दिवंगत नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को श्रद्धांजलि दी थी। उन्होंने बताया कि विदेश सचिव ने 5 मार्च को ईरानी दूतावास में जाकर शोक-पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे। MEA के मुताबिक ईरान में मौजूद भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार मदद कर रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते लौटने वालों को वीजा और सीमा पार कराने में सहायता दी जा रही है।

#### नेपाल में सिलेंडर में आधी गैस ही भरी जाएगी

**नेपाल ने कुकिंग गैस की सप्लाई सीमित करने का फैसला किया है। यह फैसला मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष के बीच संभावित सप्लाई संकट को देखते हुए लिया गया है। नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन के कार्यकारी निदेशक चंडिका प्रसाद भट्टा ने कहा कि शुक्रवार से खाली सिलेंडर में सिर्फ आधी गैस ही भरी जाएगी, ताकि मौजूदा स्टॉक ज्यादा समय तक चल सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई बार भरोसा दिलाया है कि देश में छठक्रकृकी पर्याप्त सप्लाई है, लेकिन लोगों में कमी का डर बना हुआ है। इसी वजह से देशभर में गैस भरवाने वाले प्लांट्स के बाहर खाली सिलेंडर लेकर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। नेपाल ईंधन और कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है।**

## राहुल बोले: पेट्रोलियम मंत्री ने एपस्टीन को दोस्त कहा था

### स्पीकर ने बोलने से रोका, पुरी ने कहा: एलपीजी की कमी नहीं, विपक्ष की नारेबाजी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** राहुल गांधी ने लोकसभा में गुरुवार को एलपीजी संकट का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, ह्यअभी तो दर्द की शुरूआत हुई है। रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका यह तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो यह समझ से परे है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि यह पहेली क्या है और यह समझौते से जुड़ी लगती है। तेल मंत्री खुद

कह चुके हैं कि वे एपस्टीन के दोस्त हैं। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर बिरला ने राहुल को टोका,'जिस विषय पर नोटिस दिया है उस पर बोलिए। इस पर बोलना है तो नोटिस दीजिए। इतना कहते ही विपक्ष के सांसद हंगामा करने लगे। बिरला ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से बोलने को कहा- पुरी ने जैसे ही बोलना शुरू किया एपस्टीन-एपस्टीन के नारे लगे। गुरुवार सुबह लोकसभा में विपक्ष के सांसदों ने देश में सिलेंडर संकट के मुद्दे पर हंगामा किया। सांसदों ने संसद के बाहर 'नरेंदर भी गायब, सिलेंडर भी गायब' के नारे लगाए। राहुल ने एलपीजी संकट पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था। राहुल गांधी ने सरकार से LPG की कमी से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी

#### रवि किशन बोले: कांग्रेस का काम देश को कन्फ्यूज करना है

लोकसभा में एलओपी राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, उन्हें वही बोलना था जो उन्होंने लिखा और जमा किया था, लेकिन उन्होंने क्या कहना शुरू किया और क्यों? कांग्रेस का काम देश को कन्फ्यूज करना है, और उन्होंने यह साबित कर दिया है। इस समय इस तरह की बातें करना देश को बांटने, देश को कमजोर करने की कोशिश है। हमेशा आकर स्कैंडल बनाने की उनकी आदत दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सीनियर विपक्षी नेता होने के नाते, वह इस लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं, वह भी ऐसे समय में जब सभी को सरकार का साथ देने, प्रधानमंत्री मोदी का साथ देने के लिए एक साथ आना चाहिए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# पश्चिम एशिया की जंग, मध्य- पूर्व संकट- भारत की रसोई तक पहुँचा

(/लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं)

**देश में हर साल लगभग 3 करोड़ 13 लाख टन एलपीजी की खपत होती है,जबकि घरेलू उत्पादन करीब 1 करोड़ 28 लाख टन ही है। इसका मतलब है कि लगभग 58 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भर है।इस आयात का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। यह वही समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस का प्रमुख रास्ता माना जाता है।जब इस मार्ग में युद्ध के कारण बाधा आई तो एलपीजी टैंकरों की आवाजाही रुक गई।**

-एलपीजी संकट के बीच सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का ब्रह्मास्त्र चलाया-7 साल तक की जेल

पश्चिम एशिया का मौजूदा संकट यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं

भारत के लिए मौजूदा तेलीय पदार्थ संकट,ऊर्जा आयात पर अत्यधिक निर्भरता देश की आर्थिक स्थिरता के संकट की चेतावनी व ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अवसर भी प्रदान करता है

वैश्विक स्तरपर पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बार फिर अस्थिर कर दिया है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच टकराव केवल क्षेत्रीय संघर्ष भर नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।भारत जैसे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है।खाड़ी क्षेत्र में युद्ध के कारण दुनियाँ के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक,स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बाधा उत्पन्न हो गई है। यही मार्ग विश्व के बड़े हिस्से में तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।इस मार्ग में व्यवधान का असर भारत के ईंधन बाजार पर सीधा पड़ा है। एलपीजी टैंकरों के फंस जाने,कच्चे तेल की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने और गैस आपूर्ति में अनिश्चितता के कारण भारत के ऑटो-एलपीजी तथा औद्योगिक गैस बाजार में भारी दबाव पैदा हो गया है,ऐसे में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है. नई दरों के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 115 रुपए महंगा हो गया है।स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार को 5 मार्च 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू करना पड़ा।सामान्य परिस्थितियों में यह कानून कम ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मौजूदा संकट ने इसे फिर से सक्रिय करने के लिए सरकार को मजबूर कर दिया। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि दरअसल यह संकट केवल ऊर्जा बाजार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा और आम नागरिकों की दैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआहै।भारत में करोड़ों परिवार रसोई गैस पर निर्भर हैं और औद्योगिक उत्पादन भी ऊर्जा आपूर्ति से सीधे जुड़ा हुआ है।ऐसे में पश्चिम एशिया की जंग भारत की रसोई और उद्योग दोनों के लिए सटीक गंभीर चुनौती बनकर सामने आई है।

साथियों बात अगर हम भारत की ऊर्जा निर्भरता-आयात पर आधारित संरचना को समझने की करें तो भारत दुनियाँ की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके साथ-साथ ऊर्जा की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन देश की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि घरेलू स्तर पर तेल और गैस का उत्पादन सीमित है। भारत अपनी कुल तेल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत आयात करता है।एलपीजी के मामले में भी स्थिति लगभग यही है। देश में हर साल लगभग 3 करोड़ 13 लाख टन एलपीजी की खपत होती है,जबकि घरेलू उत्पादन करीब 1 करोड़ 28 लाख टन ही है। इसका मतलब है कि लगभग 58 प्रतिशत एलपीजी आयात पर निर्भर है।इस आयात का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते भारत तक पहुंचता है। यह वही समुद्री मार्ग है जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है और खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाले तेल और गैस का प्रमुख रास्ता माना जाता है।जब इस मार्ग में युद्ध के कारण बाधा आई तो एलपीजी टैंकरों की आवाजाही रुक गई। परिणाम स्वरूप भारत में गैस आपूर्ति की स्थिति अचानक अस्थिर हो गई।सरकार के पास मौजूद बफर स्टॉक के आधार पर देश लगभग 25 से 30 दिन तक एलपीजी की जरूरत पूरी कर सकता है, लेकिन अगर आपूर्ति लंबे समय तक बाधित रहती है तो संकट और भी बहुत गंभीर हो सकता है।

साथियों बात अगर हम कतर की एलएनजी सुविधा पर हमला और आपूर्ति संकट को समझने की करें तो, ऊर्जा संकट को और गहरा करने वाली एक अन्य घटना कतर की एलएनजी सुविधा पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमले थे। कतर दुनियाँ के प्रमुख गैस निर्यातकों में से एक हैऔर भारत के लिए भी एलएनजी का महत्वपूर्ण स्रोत है।हमले में कतर की एलएनजी सुविधा को भारी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद भारत की कंपनी पेट्रोनेट एलएनजी ने कतर से गैस आपूर्ति पर फोर्स मैजर घोषित कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि अनुबंध होने के बावजूद गैस की आपूर्ति अस्थायी रूप से रोक दी गई।इस घटना ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया।एलएनजी और एलपीजी दोनों की आपूर्ति प्रभावित होने लगी, जिससे ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई।ऐसी स्थिति में सरकार के सामने दोहरी चुनौती थी एक ओर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना और दूसरी ओर बाजार में जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना।

साथियों बात अगर हम आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955- संकट में सरकार का सबसे बड़ा हथियार इसको समझने की करें तो, ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया। यह कानून भारत में आवश्यक वस्तुओं केउत्पादन वितरण और व्यापार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था।इस अधिनियम के तहत सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह किसी भी जरूरी वस्तु के उत्पादन,स्टॉक,वितरण और कीमतों पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम जनता को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमत पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।इस कानून को अक्सर सरकार का 卐ब्रह्मास्त्र卐 कहा जाता है, क्योंकि इसके तहत सरकार को असाधारण अधिकार मिलते हैं। वह कंपनियों और व्यापारियों को निर्देश दे सकती है कि वे कितना उत्पादन करें, कितना स्टॉक रखें और किस कीमत पर बिक्री करें।पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद इस कानून के तहत शुरू से ही शामिल रहे हैं। हालांकि तेल क्षेत्र में इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यही कारण है कि 2026 में एलपीजी संकट के दौरान इसका उपयोग एक बड़ा और असामान्य कदम माना जा रहा है।

साथियों बात अगर हम सरकार ने यह कानून क्यों लागू किया? इसको समझने की करें तो सरकार के इस कदम के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं।सबसे पहला कारण गैस आपूर्ति में संभावित रुकावट है। खाड़ी देशों से होने वाली गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा युद्ध के कारण प्रभावित हो गया है। अनुमान है कि भारत को मिलने वाली लगभग 60 प्रतिशत गैस आपूर्ति पर इसका असर पड़ सकता है।दूसरा कारण जमाखोरी और मुनाफाखोरी को रोकना है। जब भी बाजार में किसी आवश्यक वस्तु की कमी की आशंका होती है तो कुछ व्यापारी अधिक लाभ कमाने के लिए उसका स्टॉक जमा करने लगते हैं। इससे कृत्रिम कमी पैदा हो जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं।तीसरा कारण घरेलू उपयोग को प्राथमिकता देना है। सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन जैसे गैस घटकों का इस्तेमाल अन्य उत्पादों के बजाय एलपीजी उत्पादन के लिए करें। इससे घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकेगी। इन सभी कदमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में गैस की आपूर्ति सामान्य बनी रहे और आम लोगों को संकट का सामना न करना पड़े।

साथियों बात अगर हम एलपीजी उत्पादन और वितरण पर सरकार का नियंत्रण को समझने की करें तोआवश्यक वस्तु अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने एलपीजी उत्पादन और वितरण प्रणाली में कई बदलाव किए हैं।रिफाइनरियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने उत्पादन का बड़ा हिस्सा घरेलू एलपीजी जरूरतों को पूरा करने में लगाएं। इसके अलावा व्यापारियों और वितरकों के लिए स्टॉक लिमिट तय की जा सकती है।अगर कोई व्यापारी या कंपनी तय सीमा से अधिक स्टॉक जमाकरती है तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता हैइस कानून के तहत अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे गोदामों की जांच करें और जरूरत पड़ने पर स्टॉक जब्त कर लें।इस व्यवस्था का उद्देश्य बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना और आपूर्ति श्रृंखला को संतुलित करना है।आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है।इस कानून की धारा 7 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति या संस्था जमाखोरी, कालाबाजारी या अवैध व्यापार में शामिल पाई जाती है तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।इस सख्त प्रावधान का उद्देश्य यहसुनिश्चित करना है कि बाजार में कोई भी व्यक्ति या संस्था संकट की स्थिति का फायदा उठाकर अनुचित लाभ बिलकुल भी न कमा सके।

साथियों बात अगर हम 2022 के बाद पहली बार इतना बड़ा कदम इसको समझने की करें तो, तेल क्षेत्र में आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल बहुत कम होता है। इससे पहले 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान इसे सीमित रूप से लागू किया गया था।उस समय सरकार ने रिफाइनरियों को निर्यात रोककर घरेलू बाजार में आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए थे।लेकिन 2026 में एलपीजी उत्पादन के लिए सीधे निर्देश देना एक असाधारण कदम माना जा रहा है।विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार ऊर्जा संकट को लेकर गंभीर है और घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है।

# तिरुचिरापल्ली से नई रेल क्रांति का उदघोष

(लेखक - बिनोद कुमार सिंह)

दक्षिण, दक्कन और पूर्वी भारत को जोड़ने की दिशा में ऐतिहासिक कदम,रेल सेवाओं तक सीमित नहीं रहा। इस अवसर पर उन्होंने लगभग 5,650 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजना ओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इनमें रेलवे, ऊर्जा, पेट्रोलियम अवसंरचना, ग्रामीण सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं। भारतीय रेल केवल पटरियों पर दौड़ती हुई धातु की गाड़ियाँ नहीं है। वह भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और सांस्कृतिक संपर्क का सबसे बड़ा सेतु है।इस विशाल देश में जहाँ भौगोलिक दूरियाँ अनेक बार लोगों, बाजारों और अवसरों के बीच दूरी पैदा कर देती हैं,वहाँ रेल व्यवस्था उन्हें जोड़ने वाली जीवनरेखा का कार्य करती है।जब भी कोई नई रेल सेवा शुरू होती है,तो वह केवल एक परिवहन सुविधा का विस्तार नहीं होती,बल्कि लाखों लोगों के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खोलती है।तमिलनाडु के ऐतिहासिक नगर तिरुचिरापल्ली ने आज ऐसा ही एक महत्वपूर्ण क्षण देखा,जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अमृत भारत एक्सप्रेस,दो एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और एक यात्री ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इसके साथ ही केरल के एर्णाकुलम से एक और पैसेंजर ट्रेन सेवा भी शुरू की गई। इन रेल सेवाओं के आरंभ के साथ दक्षिण भारत,दक्कन और पूर्वी भारत के बीच संपर्क का एक नया अध्याय खुल गया है।प्रधानमंत्री की इस यात्रा का महत्व केवल रेल सेवाओं तक सीमित नहीं रहा।इस अवसर पर उन्होंने लगभग 5,650 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास भी किया।इन परियोजनाओं में रेलवे, ऊर्जा,पेट्रोलियम अवसंरचना, ग्रामीण सड़क संपर्क और औद्योगिक विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाएँ शामिल हैं।यह पूरा कार्यक्रम इस बात का संकेत देता है कि आधुनिक भारत का विकास अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं रह सकता,बल्कि उसे देश के हर क्षेत्र तक समान रूप से पहुँचना होगा।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय रेल केवल परिवहन का साधन नहीं है,बल्कि यह देश की प्रगति और सामाजिक एकता की महत्वपूर्ण धुरी है।उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पिछले वर्षों में रेलवे के व्यापक आधुनिकीकरण, नई ट्रेनों की शुरुआत,स्टेशन पुनर्विकास और रेलवे लाइनों के विद्युतीकरण जैसे कदमों ने यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान की है। उनके अनुसार विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के छोटे-छोटे शहर और कस्बे भी मजबूत परिवहन नेटवर्क से जुड़ेंगे। इस संदर्भ में पोदानूर-धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दक्षिण भारत का औद्योगिक शहर कोयंबटूर लंबे समय से देश के प्रमुख विनिर्माण केंद्रों में गिना जाता है।कपड़ा उद्योग,मशीन टूल्स,पंप निर्माण और छोटे-मध्यम उद्योगों की विशाल श्रृंखला ने इस शहर को दक्षिण भारत की औद्योगिक राजधानी जैसा स्थान दिलाया है। यहाँ के कारखानों की मशीनों की निरंतर आवाज़ केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था का संकेत नहीं है, बल्कि यह भारत के औद्योगिक तंत्र की धड़कन भी है।फिर भी एक विडंबना लंबे समय से बनी हुई थी कि इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र होने के बावजूद कोयंबटूर का पूर्वी भारत के खनिज और ऊर्जा क्षेत्र से सीधा रेल संपर्क नहीं था।अब यह स्थिति बदल गई है।पोदानूर से धनबाद तक चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस पहली बार दक्षिण भारत के इस औद्योगिक क्षेत्र को झारखंड के कोयला और इस्पात क्षेत्र से सीधे जोड़ती है।पोदानूर जंक्शन कोयंबटूर का दूसरा प्रमुख रेलवे केंद्र है और यही इस नई ट्रेन का प्रारंभिक स्टेशन है। इसके कुछ ही समय बाद यह कोयंबटूर जंक्शन पहुँचती है, जिससे यात्रियों को इस सेवा का लाभ लेने के लिए दो प्रमुख स्टेशन उपलब्ध हो जाते हैं। पहले कोयंबटूर या तिरुप्पुर से झारखंड और पूर्वी भारत जाने वाले यात्रियों को चेन्नई,विजयवाड़ा या अन्य बड़े जंक्शनों पर ट्रेन बदलनी पड़ती थी। इससे यात्रा लंबी,जटिल और थकाऊ हो जाती थी।नई अमृत भारत एक्सप्रेस इस व्यवस्था को सरल और सुगम बनाती है। यह ट्रेन अपने मार्ग में सेलम, रेनिगुंटा,विजयवाड़ा,झारसुगुड़ा और राँची जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है।इस प्रकार यह रेल सेवा केवल दो शहरों को नहीं जोड़ती,बल्कि दक्षिण भारत के औद्योगिक गलियारे और पूर्वी भारत की ऊर्जा पट्टी के बीच एक नया आर्थिक सेतु स्थापित करती है। कोयंबटूर और तिरुप्पुर की पहचान केवल उद्योगों से नहीं है।यह क्षेत्र देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों का भी प्रमुख केंद्र है।झारखंड,बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से हजारों युवा रोज़गार की तलाश में यहाँ आते हैं और करघों,कारखानों तथा निर्माण स्थलों पर काम करते हैं।उनके श्रम से ही इस क्षेत्र की औद्योगिक मशीनरी निरंतर गतिशील बनी रहती है।इन श्रमिकों के लिए अपने घर लौटना कई बार एक कठिन निर्णय बन जाता था।दो हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी,कई बार ट्रेन बदलने की मजबूरी, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म और अनिश्चित समय - यह सब उस यात्रा को और अधिक कठिन बना देता था जो पहले से ही भावनात्मक रूप से भारी होती है। अमृत भारत एक्सप्रेस उनके लिए घर लौटने की इस यात्रा को सरल और सुगम बनाती है।अमृत भारत एक्सप्रेस को विशेष रूप से सामान्य यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।यह पूरी तरह गैर-एसी,किफायती किराए वाली और बिना डायनामिक किराया प्रणाली वाली ट्रेन है। इसका उद्देश्य उन लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा देना है जिनके लिए रेल ही सबसे विश्वसनीय और सुलभ साधन है। आधुनिक स्लीपर और जनरल कोच,बेहतर बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता और अपेक्षाकृत अधिक गति-ये सभी सुविधाएँ अब उन यात्रियों को भी उपलब्ध हो रही हैं जिन्हें पहले केवल प्रीमियम ट्रेनों में मिलने वाली सुविधाएँ ही मिलती थीं। दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष कोच भी इस सेवा का हिस्सा हैं, जिससे यात्रा अधिक समावेशी बनती है।दक्षिण भारत के लिए एक और महत्वपूर्ण रेल सेवा नागर कोइल-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में शुरू हुई है।भारत के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी के निकट स्थित नागरकोइल लंबे समय से तीर्थयात्रियों,मछुआरों और समुद्री जीवन से जुड़े समुदायों का प्रमुख क्षेत्र रहा है। फिर भी यह क्षेत्र दक्कन के बड़े आर्थिक केंद्रों से अपेक्षाकृत दूर रहा।नागरकोइल से हैदराबाद की यात्रा अक्सर लंबी और जटिल होती थी, जिसमें कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी।नई अमृत भारत एक्सप्रेस इस दूरी को कम करते हुए तमिलनाडु,आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अनेक जिलों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती है।यह रेल सेवा विद्यार्थियों, कामगारों,व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए नई संभावनाएँ खोलती है।

## संपादकीय

# जो जीवन नहीं है जल

अक्सर कहा जाता है कि जल ही जीवन है। लेकिन यह जल यदि दूषित हो तो क्या इसे जीवन कहा जा सकता है? यूं तो देश के गांवों में महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन जोर-शोर से चलाया जाता रहा है। लेकिन यह बात परेशान करती है कि पेयजल का बड़ा हिस्सा प्रदूषित पाया गया है। लोग सेहत के लिये हानिकारक जल पीने को मजबूर हैं। फलत- इससे उत्पन्न बीमारियों की चुनौतियों का सामना करने को बाध्य होते हैं। यह हमारे नीति-नियंताओं की विफलता ही कही जाएगी कि देश के करोड़ों लोग आज भी स्वच्छ जल की उपलब्धता से वंचित हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि देश के तमाम इलाकों में लिए गए दूषित पेयजल नमूनों के करीब दो तिहाई हिस्से को शुद्ध करने के प्रयास नहीं हुए हैं। जो इस बात को दर्शाता है कि आज भी देश के करोड़ों लोग स्वच्छ पेयजल हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति हमारे विकास के मॉडल व तरक्की के दावों की तार्किकता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यही वजह है कि दूषित जल से होने वाले रोगों का दायरा बढ़ रहा है। यह अच्छी बात है कि जोर-शोर से घर-घर नल से जल पहुंचाने की सार्थक पहल की गई। निस्संदेह, हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसे अपने घर में स्वच्छ पेयजल मिले। इसी मकसद से साल 2019 में जल जीवन मिशन को सिरे चढ़ाया गया था। लेकिन इस योजना के सुरक्षित तरीके से संचालन और स्वच्छ जल आपूर्ति को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। यह हकीकत है कि जब लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता तो कई तरह के रोगों के पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। कहा भी जाता है कि हमारे अधिकांश रोग पेट से ही शुरू होते हैं। खासकर बच्चों व बुजुर्गों के लिये यह एक बेहद संवेदनशील मामला है। जिससे बचने के लिये स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है। देश में बार-बार स्वच्छ शहर का खिताब हासिल करने वाले मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में पिछले दिनों प्रदूषित पेयजल से होने वाली मौतों ने देश में खतरे की घंटी बजायी। घटना ने स्पष्ट संकेत दिया कि यदि इस दिशा में व्यापक स्तर पर प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में देश के सामने गंभीर स्वास्थ्य चुनौती पैदा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीणों तक पहुंचाए जा रहे पेयजल की गुणवत्ता की परख के लिये पानी के सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही स्वच्छ पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह लोगों के खिलाफ एक्शन भी लिया जाता है। यहां उल्लेखनीय है कि बीते साल जल जीवन मिशन के तहत तमाम राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों में पेयजल सैंपलों की जांच की गई। लेकिन चिंताजनक स्थिति यह है कि कुल नमूनों के छब्बीस प्रतिशत को ही शुद्ध करने के प्रयास हुए हैं। आखिर देश के किसी भी भाग में पेयजल के सैंपल लेने का क्या औचित्य रह जाता है, जब प्रदूषित जल को लेकर उपचारात्मक प्रयास न किए जाएं। सवाल केवल ग्रामीण इलाकों के लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने का ही नहीं है, शहरी इलाकों में शुद्ध जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। गाहे-बगाहे देश के शहरी इलाकों में भी प्रदूषित जल पीने से बीमार होने की खबरें आती रहती हैं। लेकिन स्थानीय निकाय इस चुनौती को गंभीरता से नहीं लेते। संपन्न लोग तो आरओ तथा फिल्टर आदि वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन कमजोर वर्ग व सामान्य लोग दूषित पानी के उपयोग के लिये मजबूर होते हैं। स्वच्छ जल प्राप्त करना हर नागरिक का मौलिक व जीवन रक्षा का अधिकार जैसा है, जिसे गंभीरता से लेना चाहिए।

# जीव परमेश्वर की परा शक्ति




जीव परमेश्वर की परा प्रकृति (शक्ति) है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप- स्थूल (पृथ्वी आदि) तथा सूक्ष्म (मन आदि) अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्य के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की परा शक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती, जब तक परा शक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अत- जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है।

वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिहीन मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद्भागवत में जीव तथा भगवान के अन्तर को इस प्रकार बताया गया है- 'ि परम शात! यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शात एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किन्तु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए, तब वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अत- वास्तविक मुक्ति आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे।

परमेश्वर कृष्ण एकमात्र नियन्ता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किन्तु वे शक्ति की मात्रा के विषय में समान नहीं हैं। स्थूल व सूक्ष्म अपरा शक्ति का उपभोग करते हुए परा शक्ति (जीव) को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इसका कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है। माया के प्रभाव में अहंकार सोचता है, मैं ही पदार्थ हूं और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है किंतु जब वह सारे भौतिक विचारों से मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाती है, तो पूर्णतया कृष्णभावनाभावित या बंधनमुक्त हो जाती है।

## विचार मंथन

# लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के मायने

(लेखक-सनत जैन)

हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विरुद्ध विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पर सदन मे सभी राजनीतिक दलों के संसद सदस्यों ने चर्चा कर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर अपना-अपना मत रखा है। भारतीय संसद की कार्य प्रणाली और संसदीय परंपराओं को लेकर गंभीर बहस हुई है। पिछले 7 वर्षों से लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली पड़ा हुआ है। इस पर भी विपक्षी दल के सदस्यों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष को सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का नेता माना जाता है। नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से बोलने नहीं दिया गया था। सदस्यों को बोलने के दौरान बार-बार टोंका जाता है। तरह-तरह के नियम बताकर सांसदों को अपनी बात नहीं कहने दी जाती है। बिना चर्चा और बिना प्रक्रिया के सदन से जो बिल पास किये जा रहे हैं। सत्र की अवधि लगातार कम किए जाने के कारण सदस्य अपनी बात संसद में नहीं रख पाते हैं इसको लेकर संसद सदस्यों में पिछली कई वर्षों से नाराजी देखने को मिल रही थी। सत्ता पक्ष जिस तरह से विपक्षी सदस्यों को बोलने से रोकता था आसंदी का सत्ता पक्ष के लिए अलग व्यवहार और विपक्ष के लिए अलग व्यवहार अविश्वास प्रस्ताव का कारण बना। लोकसभा अध्यक्ष का पद संविधान और संसदीय लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष सभी सदस्यों का संरक्षक होता है। वह सरकार या किसी पार्टी का नहीं होता है। यह पद सदन की कार्यवाही निष्पक्ष और संतुलित ढंग से संचालित हो। सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार मिले। जो भी कानून और नियम बनाए जा रहे हैं उनमें सभी पक्षों की राय ली जाए। यह दायित्व लोकसभा के अध्यक्ष का होता है। सदन में किसी भी विषय पर स्वतंत्रता से संसद सदस्य अपनी बात रख सकते हैं। यदि कुछ नियमों के विपरीत होता है तो उसे हटाने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है लेकिन बोलने के पहले ही उसे रोक दिया जाए। पिछले 12 वर्षों में यह बहुत बार देखने को मिला है। यही अति अविश्वास का सबसे बड़ा कारण बनी। सत्ता पक्ष बहुमत में होता है। विपक्ष अल्पमत में होता है। ऐसी स्थिति में यह परंपरा रही है कि अध्यक्ष सरकार और विपक्ष के बीच जब टकराव होता है तो ऐसी स्थिति में वह मध्यस्थता करके तथा अपने अधिकारों का उपयोग करके सही निर्णय लेकर सदन की कार्यवाई को संचालित करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पिछले कुछ वर्षों से सत्ता पक्ष का दबाव आसंदी पर देखा जा रहा था। ऐसे में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल एक व्यक्ति पर सवाल नहीं बल्कि संसद की कार्यशैली और लोकतांत्रिक संवाद और जवाबदेही का भी मामला है। संसद सदस्यों को सदन में स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलता है। बोलते समय उन्हें बीच में रोक दिया जाता है। सेंसेक्स सदस्यों को थोक के भाव में निलंबित कर दिया जाता है। सदस्यों का कहना था, अध्यक्ष को सभी दलों के सांसदों के साथ तथा नेता प्रतिपक्ष के साथ समान दृष्टिकोण रखना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में सत्ता पक्ष को अधिक अवसर और संरक्षण देने का आरोप अध्यक्ष पर लगाया गया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा अध्यक्ष ने सदन की मर्यादा, सदन की कार्यवाई सुचारू रूप से चले, सदन में व्यवधान ना हो। इसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यक कदम उठाए गये हैं। सत्ता पक्ष का आरोप था विपक्ष की लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण अध्यक्ष को कठोर निर्णय लेने पड़े हैं। भारतीय संसदीय परंपरा में लोकसभा अध्यक्ष को निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। संसद से जो भी कानून पास होते हैं उनमें अध्यक्ष की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। भारतीय संविधान में अध्यक्ष के पद को दलगत राजनीति से अलग रखा गया है। यदि अध्यक्ष की निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक संकेत है। इस विवाद का समाधान केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है, संसद की गरिमा, सदस्यों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधायी कार्य की गुणवत्ता के बीच संतुलन बनाया जाए। संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है। यहां संवाद,बहस और असहमति को स्थान मिलना ही चाहिए। सभी सदस्यों को संसद में वह सभी बात कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो वह संसद के बाहर किसी कारण से नहीं बोल पाते हैं। यदि यह परंपरा कमजोर होती है, तो उसका प्रभाव पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ना तय है। पिछले 75 वर्षों में भारत की संसद ने बार-बार यह साबित किया है। सत्ता को नियंत्रित करने एवं नियम और कानून का बेहतर निर्माण हो इस दिशा में जो कार्य पहले हुए हैं वह बहुत संतोष जनक रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सत्ता पक्ष आसंदी पर हावी हो रही है, उसके कारण अब यह टकराव चरम पर पहुंच गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के प्रति दुश्मनों के समान व्यवहार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के पास बहुमत है ऐसे में सभी जानते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना विपक्ष के लिए संभव नहीं। हुआ भी यही ध्वनिमत से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, लेकिन जिस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ उसने अपनी नाराजी सत्ता पक्ष और आसंदी को जता दी। पिछले 7 वर्षों से उपाध्यक्ष के पद पर किसी का चयन नहीं हो पाया है अविश्वास प्रस्ताव के दौरान यह बात भी खुलकर सामने आई की दोनों पद होना अत्यंत आवश्यक हैं।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## अल्फाग्रेप को मिली सेबी से म्यूचुअल फंड कारोबार की मंजूरी

**नई दिल्ली ।** निवेश कंपनी अल्फाग्रेप को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। इस कदम के साथ कंपनी खुदरा परिसंपत्ति प्रबंधन क्षेत्र में प्रवेश करेगी और आम निवेशकों को उन्नत निवेश उत्पादों तक पहुंच प्रदान करेगी। कंपनी का उद्देश्य है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से एल्गोरिदम और तकनीकी निवेश उपकरण को व्यापक निवेशकों तक पहुंचाया जाए। यह निवेश मुख्य रूप से उन उत्पादों पर आधारित होगा, जो अब तक संस्थागत निवेशकों और उच्च संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए ही सीमित थे। म्यूचुअल फंड इकाई का संचालन अल्फाग्रेप इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करेगी। यह इकाई फरवरी 2026 तक अपने विशेष वैकल्पिक निवेश कोष और खंड प्रबंधन सेवाओं के प्लेटफॉर्म के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर रही है। कंपनी का संचालन गिफ्ट सिटी में भी होता है। नए म्यूचुअल फंड कारोबार का फोकस परिमाणात्मक इक्विटी और मिश्रित निवेश रणनीतियों पर होगा। इसमें उन्नत गणितीय मॉडल, कृत्रिम मेधा (AI) और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य है निवेशकों को अधिक संगठित और रणनीतिक निवेश विकल्प प्रदान करना।

## जीएसपी क्रॉप साइंस का 400 करोड़ का आईपीओ 16 मार्च को खुलेगा

**नई दिल्ली ।** कृषि रसायन कंपनी जीएसपी क्रॉप साइंस लिमिटेड का 400 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 16 मार्च को खुलेगा। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि आईपीओ के लिए 304-320 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया है। आईपीओ 16 मार्च को खुलेगा और 18 मार्च को संपन्न होगा। बड़े (एंकर) निवेशक 13 मार्च को बोली लगा पाएंगे। अहमदाबाद स्थित इस कंपनी का आईपीओ 240 करोड़ रुपये के नए शेयर और 160 करोड़ रुपये के 50 लाख शेयर की बिक्री पेशकश (ओएफएस) का संयोजन है। नए निर्गम से हासिल 170 करोड़ रुपये की राशि का इस्तेमाल ऋण भुगतान के लिए किया जाएगा। एक हिस्सा सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए रखा जाएगा।कंपनी का शेयर 24 मार्च को बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है। जीएसपी क्रॉप साइंस एक अनुसंधान-केंद्रित कृषि रसायन कंपनी है। इसे भारत में कीटनाशकों, शाकनाशियों, कवकनाशी और पादप वृद्धि नियामकों के विकास एवं निर्माण में 39 वर्ष से अधिक का अनुभव है।

## ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर के पार, ईरानी हमलों से हुआ महंगा

**बैंकॉक ।** अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत बृहस्पतिवार तड़के 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई। कुछ दिन पहले यह लगभग 120 डॉलर तक पहुंच चुकी थी, जिससे वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास वाणिज्यिक पोतों पर ईरानी हमलों के कारण आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके चलते ब्रेंट क्रूड की कीमत में नौ प्रतिशत से अधिक की तेजी आई। अमेरिका के मानक कच्चे तेल का दाम भी लगभग 95 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति में व्यवधान का असर सीधे तेल की कीमतों पर पड़ रहा है। तेल की बढ़ती कीमतों से वैश्विक ऊर्जा बाजार और उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ सकता है, जिससे ईंधन महंगा होने की संभावना है।

# आईईए का ऐतिहासिक फैसला, 400 मिलियन बैरल तेल बाजार में रिलीज़

**- कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना**

नई दिल्ली । पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की आपूर्ति पर दबाव के बीच इंटरनेशनल इनर्जी एजेंसी (आईईए) ने इतिहास में सबसे बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी के 32 सदस्य देशों ने मिलकर 400 मिलियन बैरल कच्चा तेल रणनीतिक भंडार से बाजार में जारी करने का निर्णय लिया। यह आईईए द्वारा अब तक किया गया सबसे बड़ा ऑयल रिलीज़ है। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने की संभावना है। आईईए के प्रस्ताव को मंगलवार को सदस्य देशों की बैठक में पेश किया गया और बुधवार को सभी 32 देशों ने सर्वसम्मति से समर्थन दिया। अगर कोई भी देश वीटो करता, तो प्रस्ताव पारित नहीं होता। अमेरिका और जापान इस पहल में सबसे बड़ा योगदान देंगे, जबकि यूरोपीय देशों और जर्मनी ने भी भागीदारी की पुष्टि की है। हाल ही में कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, जो चार साल का उच्चतम स्तर है। वैश्विक स्तर पर लगभग 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई बाधित होने का अनुमान है। आईईए सदस्य देश एक महीने में करीब 100 मिलियन बैरल तेल बाजार में उतारने की योजना बना रहे हैं, जिससे रोजाना लगभग 3.3 मिलियन बैरल तेल उपलब्ध हो सकेगा। इस कदम से ब्रेंट और डब्ल्यूटीआई क्रूड की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। आईईए का मुख्यालय पे रिस, फ्रांस में है और यह वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर रखने के लिए रणनीतिक फैसले लेती है। 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान आईईए ने 182 मिलियन बैरल तेल जारी किया था, लेकिन यह अब तक का सबसे बड़ा रिलीज़ है।

## रुपया गिरावट पर बंद

**मुंबई ।**

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गुरुवार को भारतीय रुपया 19 पैसे की गिरावट के साथ ही 92.20 पर बंद हुआ। आज सुबह रुपया 31 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.32 पर पहुंच गया। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के कारण विदेशी पूंजी की निकासी, वैश्विक कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और डॉलर के मजबूत रुख से घरेलू मुद्रा दबाव में है। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार घरेलू शेयर बाजारों में सत्र की कमजोर शुरुआत ने स्थानीय मुद्रा पर और दबाव डाला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.25 पर खुला। फिर और गिरावट के साथ 92.32 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 31 पैसे कम है। रुपया बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 92.01 पर बंद हुआ था। इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.47 पर रहा।

## लखनऊ में एलपीजी संकट, चूल्हे बुझे, लकड़ी-कोयले की मांग बढ़ी

**- शादियों और दावतों का बिगड़ा बजट, बड़े रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू को आधा किया**

**लखनऊ ।** नवाबों के शहर लखनऊ में एलपीजी (गैस) सिलेंडर की किल्लत ने आम जनता की परेशानियां बढ़ा दी हैं। शहर में गैस न मिलने के कारण घरों के चूल्हे बुझ गए हैं और लोग अब लकड़ी व कोयले पर खाना बनाने को मजबूर हैं। स्ट्रीट फूड वेंडर्स, ढाबा मालिक और टिफिन सेवाएं भी गैस की कमी से प्रभावित हैं। बाजार में लकड़ी और कोयले की मांग में 50-60 फीसदी की वृद्धि हुई है। पिछले दो दिनों में लगभग 450 नई मिट्टी की भट्टियों की मांग दर्ज की गई है। शहर के बड़े रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू को आधा कर दिया है, केवल चुनिंदा व्यंजन ही बन पा रहे हैं। शादी-शादी में रोजाना 1200-1500 कार्यक्रमों के लिए कैटरर्स को लकड़ी की आग पर खाना पकाना पड़ रहा है। इससे न केवल समय बढ़ा है बल्कि लागत भी अधिक हुई है। हलवाई अब पारंपरिक चूल्हों का सहारा ले रहे हैं, जिससे ग्राहकों के लिए भोजन तैयार करने की प्रक्रिया धीमी हो गई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र और पीजी में रहने वाले लोग भी प्रभावित हैं। इंडक्शन चूल्हों पर बड़े पैमाने पर खाना बनाने से भारी बिजली बिल का डर बना हुआ है। टिफिन संचालक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि गैस की आपूर्ति नहीं हुई, तो उन्हें सेवाएं बंद करनी पड़ सकती हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं। जिला प्रशासन ने निगरानी बढ़ाई है और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। ईंधन की कमी के कारण नगर निगम के वाहनों की सफाई व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी है।

# शेयर बाजार गिरावट पर बंद , निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपये डूबे

**सेंसेक्स 829 , निफ्टी 228 अंक गिरा**

**मुम्बई ।**

भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को गिरावट पर बंद हुआ। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कामजोर संकेतों के बीच ही बिकवाली हावी रहने से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 829 अंक टूटकर 76,034 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 228 अंक फिसलकर 23,639 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में इस गिरावट का एक कारण ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) की कीमतों के 100 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंचने के कारण भी आया है। इससे भी निवेशकों में घबराहट का माहौल है। आज बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकर पिछले सत्र के लगभग 450 लाख करोड़ रुपये से घटकर 440 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इससे निवेशकों के एक ही सत्र में 10 लाख करोड़ रुपये डूब गये।

आज कारोबार के दौरान निफ्टी की कंपनियों में से सबसे ज़्यादा बढ़त कोल इंडिया के शेयरों में रही। इसमें 5.23 फीसदी की बढ़त रही जबकि एनटीपीसी में 2.81 फीसदी की बढ़त जबकि पावर ग्रिड में 1.61 फीसदी की बढ़त आई। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 1.47 फीसदी जबकि अडानी एंटरप्राइजेज में 1.39 फीसदी की बढ़त आई।

वहीं निफ्टी की कंपनियों में सबसे ज़्यादा गिरावट महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयरों में रही। इसमें 4.33 फीसदी की गिरावट आई। इसके अलावा क्वालिटी वॉल्स में 3.95 फीसदी जबकि आयशर मोटर्स में 3.92 फीसदी की गिरावट रही। मारुति सुजुकी में 3.61 फीसदी और बजाज फाइनेंस में 3.42 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो, ऑटो इंडेक्स 3 फीसदी से अधिक, एफएमसीजी में 1.7 फीसदी और प्राइवेट बैंक में 1.6 फीसदी गिरावट रही जबकि पावर और एनर्जी सेक्टर में 2.5फीसदी और 2फीसदी की बढ़त रही। ऑयल 3 गैस, मेटल और कैपिटल गुड्स में मामूली 0.5फीसदी की तेजी रही। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.4फीसदी गिरा और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.7फीसदी नीचे आया। वहीं आज सुबह भारतीय शेयर बाजार

गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स सुबह 76,369 अंकों के स्तर पर खुला पर खुलते ही इसमें गिरावट बढ़ने लगी। इसी तरह निफ्टी 50 भी 23,674.85 अंकों पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह तेजी से नीचे फिसलकर 23,600 अंकों के स्तर से भी नीचे 274.35 अंक की गिरावट के साथ 23,592.50 अंकों पर कारोबार करता हुआ देखा गया। आज बाजार में गिरावट का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत एशियाई कारोबार के दौरान लगभग 8 फीसदी बढ़कर 100.18 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई। तेल की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ने और कंपनियों की लागत में वृद्धि की आशंका बढ़ जाती है, जिससे निवेशकों में सतर्कता देखी जाती है।

# अमेरिका ने शुरू की भारत, चीन सहित कई व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ जांच

**- विशेष रूप से जांच अतिरिक्त उत्पादन और संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित**

**न्यूयॉर्क ।**

अमेरिका ने भारत, चीन, जापान, यूरोपीय संघ और अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशों के खिलाफ 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301(बी) के तहत जांच शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य उन विदेशी नीतियों और प्रथाओं का पता लगाना है, जो अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र पर नकारात्मक असर डाल रही हैं। विशेष रूप से यह जांच अतिरिक्त उत्पादन और संरचनात्मक अतिरिक्त क्षमता से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है। जांच के दायरे में शामिल हैं- बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, नॉर्वे, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम। यूएसटीआर जैमीसन ग्रीर ने कहा कि यह कदम अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र को विदेशी अतिरिक्त उत्पादन से बचाने और घरेलू रोजगार बढ़ाने के प्रयास का हिस्सा है। ग्रीर ने बताया कि कई देशों में उत्पादन घरेलू खपत से अधिक है, जिससे अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है और निवेश बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा` कि अमेरिका अब अपने औद्योगिक आधार को उन देशों के लिए बलिदान नहीं करेगा जो अतिरिक्त उत्पादन यहां निर्यात कर रहे हैं। यह पहल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं को

अमेरिका में फिर से स्थापित करना और उच्च वेतन वाली नौकरियों का सृजन करना है। जांच शुरू करने से पहले अंतर-विभागीय धारा 301 समिति और सलाहकार समितियों से परामर्श लिया गया। अब अमेरिका को उन देशों के साथ परामर्श करना होगा जिनकी नीतियां जांच के दायरे में हैं। टिप्पणियां जमा करने की प्रक्रिया 17 मार्च 2026 से शुरू होगी और सुनवाई 5 मई से शुरू होगी।

## अमेरिका करेगा पेट्रोल की कीमत कम करने के लिए तेल भंडार का इस्तेमाल- ट्रंप

**पेरिस ।** अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके प्रशासन के दौरान ईरान युद्ध के कारण बढ़ी पेट्रोल की कीमतों को कम करने के लिए अमेरिका के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने डब्ल्यूके आरसी लोकल-12 चैनल को साक्षात्कार में बताया कि ÷हम इसे थोड़ा कम करेंगे और फिर कीमतें नीचे आएंगी। बाद में इसे फिर से भर देंगे। ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि भंडार से कितने बैरल तेल जारी होंगे। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि उन्होंने पहले कई बार जो बाइडन के प्रशासन की आलोचना की थी, जो पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए इस भंडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व अमेरिका का आपातकालीन तेल भंडार है। इसे भू-राजनीतिक संकट, युद्ध या आपूर्ति रुकने की स्थिति में इस्तेमाल के लिए भूमिगत गुफाओं में संग्रहित किया जाता है।

# एसबीआई और एमयूएफजी बैंक ने वित्तीय साझेदारी पर हस्ताक्षर किए

**- दोनों बैंक भारतीय मिड-कॉर्पोरेट्स और एमएसएमई को जापानी कॉर्पोरेट नेटवर्क से जोड़ने में सहयोग करेंगे**

**नई दिल्ली ।**

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और जापान का एमयूएफजी बैंक ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर कर ` दिए हैं। यह समझौता मुख्य रूप से विलय और अधिग्रहण (एमएंडए), विमानन और रियल एस्टेट फाइनेंस क्षेत्रों पर केंद्रित है। दोनों बैंक भारतीय मिड-कॉर्पोरेट्स और एमएसएमई को जापानी कॉर्पोरेट नेटवर्क से जोड़ने में सहयोग करेंगे। एसबीआई ने बताया कि नए आरबीआई दिशानिर्देशों के तहत उसकी ऋण देने की अधिकतम सीमा लगभग 94,000 करोड़ रुपए है। साझेदारी के तहत दोनों बैंक एमएंडए एडवाइजरी, ट्रेड फाइनेंस और रिटेल बैंकिंग सॉल्यूशंस पर सहयोग करेंगे। इसके अलावा, जापानी कॉर्पोरेट-आधारित संभावित आयात-निर्यात लेन-देन की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। एसबीआई की भारतीय बाजार में गहरी पकड़ और एमयूएफजी के वैश्विक नेटवर्क का संयोजन इस साझेदारी को खास बनाता है। दोनों बैंक अपनी पूरक क्षमताओं का उपयोग करके सीमा-पार पूंजी प्रवाह को आसान बनाएंगे। इससे न केवल नए वित्तीय अवसर उत्पन्न होंगे, बल्कि भारत और जापान की अर्थव्यवस्थाओं में स्थायी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि बैंक जापानी ऋणदाताओं के साथ एमएंडए फ्राइनेंसिंग पर चर्चा कर रहा था। एमयूएफजी बैंक के भारत और श्रीलंका क्षेत्रीय कार्यकारी ताकुया सेनो ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर सबसे आकर्षक विकास बाजारों में से एक है। साझेदारी के माध्यम से, एमयूएफजी भारत में इनबाउंड निवेश और भारतीय कॉर्पोरेट्स के आउटबाउंड विस्तार दोनों का समर्थन करेगा।

## टेक्सास में नई रिफाइनरी की घोषणा, रिलायंस के निवेश का दावा

**अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 300 अरब डॉलर के करार का किया जिक्र**

**वाशिंगटन ।**

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने टेक्सास के ब्राउंसे विले में नई रिफाइनरी स्थापित किए जाने की घोषणा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया कि इस परियोजना में` रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) के निवेश से लगभग 300 अरब डॉलर का करार किया गया है। इस निवेश के तहत ब्राउंजविल में एक बड़ी रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बताई गई है। हालांकि, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस परियोजना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ट्रंप के अनुसार, इस रिफाइनरी का निर्माण अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग (एएफआर) नामक कंपनी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना अमेरिका में पिछले लगभग 50 वर्षों में बनने वाली पहली नई रिफाइनरी होगी। ट्रंप का कहना है कि इस रिफाइनरी के शुरू होने से ऊर्जा निर्यात में वृद्धि होगी, बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे और आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यह घोषणा ऐसे समय में सामने आई है जब इं डिया और अमे रिका के बीच फरवरी 2026 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत ने अगले पांच वर्षों में ईंधन सहित लगभग 500 अरब डॉलर के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की मंशा जताई थी, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकती है।

## होर्मुज संकट के बीच भारत ने बढ़ाए वैकल्पिक ईंधन स्रोत

**ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव से बंद हुआ होर्मुज मार्ग, भारत अन्य रास्तों से तेल-गैस मंगा रहा**

**नई दिल्ली ।** पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के कारण रणनीतिक समुद्री मार्ग स्ट्रेट आफ होर्मुज बंद होने से भारत की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत ने वैकल्पिक समुद्री मार्गों से कच्चा तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) मंगाने की व्यवस्था तेज कर दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में कच्चे तेल के दो कार्गो जहाज भारत पहुंचने वाले हैं, जबकि एलएनजी के दो अन्य जहाज भी रास्ते में हैं। उन्होंने कहा कि पहले भारत के कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 55 प्रतिशत हिस्सा होर्मुज मार्ग से अलग रास्तों से आता था, जो अब बढ़कर करीब 70 प्रतिशत हो गया है। सरकार ने घरेलू जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तेल कंपनियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 5 मार्च को जारी आदेश के बाद भारतीय रिफाइनरियों ने एलपीजी उत्पादन लगभग 25 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। साथ ही पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रोपेन और ब्यूटेन का उपयोग फिलहाल रोक दिया गया है ताकि घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है, जिनमें से करीब 90 प्रतिशत आपूर्ति सामान्यतः होर्मुज मार्ग से होती है। प्राकृतिक गैस की कुल खपत लगभग 18.9 करोड़ मानक घन मीटर प्रतिदिन है, लेकिन भारत के प्रमुख एलएनजी आपूर्तिकर्ता कतर इनर्जी के उत्पादन रुकने से करीब 4.6 करोड़ मानक घन मीटर की आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस बीच विदेश मंत्रालय के अनुसार संघर्ष क्षेत्र में एक वाणिज्यिक जहाज पर हमले में दो भारतीय नाविकों की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य लापता है। फिलहाल परे सियन गल्फ क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले 28 जहाज और 700 से अधिक भारतीय नाविक मौजूद हैं। सरकार का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और घबराने की जरूरत नहीं है।

# भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा, एसएंडपी की चेतावनी

**- भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल 10 दिन की खपत के लिए पर्याप्त**

**नई दिल्ली ।**

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने चेतावनी दी कि भारत की अर्थव्यवस्था ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से जोखिम में है। भारत अपने कच्चे तेल की लगभग 88 फीसदी जरूरतें आयात करता है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। देश में प्रतिदिन 58 लाख बैरल तेल की खपत होती है, जिसमें से 25-27 लाख बैरल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज मार्ग से आता है। एलपीजी और एलएनजी का भी एक बड़ा हिस्सा इसी मार्ग पर निर्भर है। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार केवल 10 दिन की खपत के लिए पर्याप्त हैं, जबकि वाणिज्यिक भंडार 65 दिन का ही समर्थन कर सकता है। एलपीजी और एलएनजी का भंडार और भी कम है, क्रमशः केवल 25-30 दिन और 10-12 दिन की जरूरतें पूरी कर पाता है। सीमित भंडार के कारण, वैश्विक आपूर्ति संकट या कीमतों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। भारत समुद्री

मार्गों पर अत्यधिक निर्भर है, लेकिन कुछ विविधीकरण किया जा रहा है। रूस से 11 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात जारी है, जबकि वेनेजुएला से हाल ही में 1.42 लाख बैरल प्रतिदिन का आयात फिर से शुरू हुआ। यह कदम आपूर्ति संकट के समय विकल्प प्रदान करने की दिशा में है। एसएंडपी का कहना है कि ऊर्जा आयात पर अधिक निर्भरता वाले एशियाई देशों में आर्थिक जोखिम अधिक है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

# टी20 विश्व कप के बाद गौतम गंभीर ने गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब में टेका माथा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब गए और माथा टेका। रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड पर 96 रन की शानदार जीत के बाद भारत ने रिकॉर्ड तीसरा पुरुष टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतकर इतिहास रच दिया और टाइटल बचाने और इसे अपने देश में जीतने वाली पहली टीम बन गई।

उनका यह दौरा पूर्व भारतीय क्रिकेटर और TMC MP कीर्ति आजाद की आलोचनाओं के बीच हुआ है जिन्होंने रविवार को अहमदाबाद में टीम की जीत के बाद टी20 वर्ल्ड कप 2026 ट्रॉफी को मंदिर ले जाने के लिए गंभीर समेत भारतीय लीडरशिप की आलोचना की थी। आजाद के कमेंट्स पर रिएक्ट करते हुए गंभीर ने कहा, 'लगता है कि इस सवाल का जवाब देना भी सही नहीं है। यह पूरे देश के लिए एक बड़ा पल है।'

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम वर्ल्ड कप जीत का जश्न मनाएं और इसीलिए मैं कुछ बातें कहता हूं; कुछ बातों को उठाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बातें सिर्फ आपकी कामयाबी को कमजोर करेंगी। अगर आप उन 15 खिलाड़ियों की कामयाबी और उनकी कोशिशों को कमजोर करना चाहते हैं जो लड़कों के साथ सही नहीं है। अगर आप ऐसा बयान देते हैं, तो आप सचमुच अपने ही खिलाड़ियों और अपनी ही टीम को नीचा दिखा रहे हैं, जो नहीं किया जाना चाहिए।'

कीर्ति ने इस कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कोई खिलाड़ी या खेल किसी धर्म या जाति का नहीं होता। कीर्ति आजाद ने कहा था, 'जब टीम इंडिया जीती जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे, तो 140 करोड़ लोग उत्साहित थे। एक खिलाड़ी या खेल किसी धर्म या जाति से नहीं बल्कि सिर्फ खेल से जुड़ा होता है। एक खिलाड़ी के तौर पर मैं कहता हूं कि टीम इंडिया ने भारत को जिताया। टीम इंडिया जीती, और यह भारत के लोगों के लिए गर्व की बात है।'

भारत के हेड कोच के तौर पर गंभीर के पास अब चैंपियंस ट्रॉफी 2025, एशिया कप 2025, और ङ्ग20 वर्ल्ड कप 2026 के टाइटल हैं, साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मेंटर के तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का टाइटल भी है। अपने खेलने

के दिनों में टी20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वर्ल्ड कप, एशिया कप और IPL जीतने के बाद दिल्ली में जन्मे इस खिलाड़ी ने अपने लिए कामयाबियों की एक लंबी लिस्ट बनाई है।

# सूर्यकुमार ने अभिषेक से कहा था, 8 बार शून्य पर आउट हुआ तो भी पारी शुरु करेगा

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य कोच गौतम गंभीर मुश्किल दौर से गुजर रहे खिलाड़ियों का बचाव करते रहे हैं। इसी का परिणाम है कि टीम को खिताबी जीत मिल रही है। टी20 विश्कप में सूर्या ने खराब दौर से गुजर रहे युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का हौंसला बढ़ाया था। अभिषेक तीन मैच में लगातार शून्य पर आउट होने के कारण भारी दबाव में थे और उन्हें बाहर किये जाने की मांग उठ रही थी पर सूर्यकुमार ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसी कारण अभिषेक ने फाइनल में 18 गेंदों पर ही अर्धशतक लगा दिया। सूर्यकुमार के अनुसार उन्होंने इस बल्लेबाज से कहा था कि कि अगर वह 9 में से 8 मैचों में भी खाता नहीं खोल पाएगा तो भी उसे फाइनल में पारी की शुरुआत के लिए भेजा जाएगा। इसी कारण अभिषेक का आत्मविश्वास बना रहा और वह निडर होकर फाइनल खेलने उतरे।

अभिषेक के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत खराब रही थी। शुरुआत में पेट दर्द के कारण वह पहले मैच से बाहर रहे। इसके बाद के मैचों में वह तीन बार शून्य पर आउट हुए। इसी कारण पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने भी उन्हें फाइनल से बाहर करने को कहा था। गावस्कर का कहना था कि अभिषेक अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं और एक ही गलती को दोहरा रहे हैं। हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिर भी उन्हें फाइनल में मौका दिया और अभिषेक ने उनके भरोसे को सही साबित करते हुए 18 गेंदों में ही टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्धशतक जड़ दिया था।सूर्यकुमार ने कहा, ÷मैंने उससे कहा था, 'इस विश्व कप में 9 गेम हैं, भले ही आप उनमें से आठ में विफल हो जाएं, फिर भी मैं गारंटी लेता हूं कि आप फाइनल में पहली गेंद खेलोगे।'

# दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमे सुरक्षित रवाना : आईसीसी

**दुबई (एजेंसी)।** अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार को कहा कि पुरुष टी-20 विश्वकप अभियान समाप्त होने के बाद दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीमें और उनके सहयोगी सदस्य सुरक्षित स्वदेश रवाना हो गई है। आईसीसी ने आज जानकारी दी है कि दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज टीम के सभी खिलाड़ी और उनके सहयोगी स्टाफ के सदस्य पूरी तरह से अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में, दक्षिण अफ्रीका के बाकी 29 सदस्य और वेस्टइंडीज के आखिरी 16 सदस्य अपने-अपने देशों के लिए उड़ान से रवान हो गये हैं, जिससे एक मुश्किल अभियान खत्म हो गया है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण हमने ऑपरेशनल दिक्कतों से निपटने के लिए सरकारों, एयरलाइंस, चार्टर प्रोवाइडर्स, एयरपोट 'अथॉरिटीज और हमारे मेंबर बोर्ड्स के साथ लगातार काम किया है।

बाकी सभी खिलाड़ियों और स्टाफ के लिए आगे की सुरक्षित यात्रा पक्की करना हमारा एकमात्र मकसद था और हालात बदलने के साथ-साथ इसमें लगातार बदलाव करने की जरूरत पड़ी। आईसीसी ने कहा कि हम क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका, क्रिकेट वेस्टइंडीज और उनकी पूरी टीम को इस पूरे प्रोसेस में उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा आईसीसी स्टाफ को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत मेहनत की कि सभी खिलाड़ी, स्टाफ और उनके परिवार सुरक्षित घर पहुंच सकें।

# टी20 वर्ल्ड कप : 'बैट उठाया, पानी पिलाया..', मोहम्मद सिराज के बयान ने जीता दिल, टीम स्पिरिट की दी मिसाल

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। इस ऐतिहासिक जीत के बीच टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने अपने मजाकिया अंदाज और शानदार टीम भावना से फैंस का दिल जीत लिया। प्लेइंग इलेवन का नियमित हिस्सा न होने के बावजूद सिराज ने टीम की सफलता को सबसे ऊपर रखा और अपने बयान से बता दिया कि असली टीम मैन किसे कहते हैं।

### मोहम्मद सिराज का मजाकिया जवाब हुआ वायरल

टीम इंडिया की जीत के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत के दौरान सिराज से पूछा गया कि प्लेइंग इलेवन से बाहर रहना निराशाजनक होता है, ऐसे में टीम की जीत में उनकी क्या भूमिका रही?

इस पर सिराज ने हंसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, 'हम दोनों का बहुत बड़ा रोल था... बाहर बैठकर बैक टू बैक पानी पिलाना और बैट उठाना।' सिराज की यह बात सुनकर उनके साथ खड़े कुलदीप यादव भी जोर-जोर से हंसने लगे। सिराज का यह सेल्फ-रोस्ट वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी सादगी और टीम भावना की खूब तारीफ कर रहे हैं।

### सिराज बोले- व्यक्ति नहीं, टीम सबसे बड़ी

मजाक के बाद सिराज ने टीम स्पिरिट पर बेहद अहम बात भी कही। उन्होंने कहा कि हर खिलाड़ी मैदान पर खेलना चाहता है, लेकिन अगर टीम कॉम्बिनेशन के कारण बाहर बैठना पड़े तो उसे भी सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए।

सिराज ने कहा, 'नेट में गेंदबाजी करना और ड्रेसिंग रूम का माहौल पॉजिटिव रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। कोई खिलाड़ी बड़ा नहीं होता, टीम सबसे बड़ी होती है।' उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ल्ड कप जीत को वह भगवान की स्क्रिप्ट मानते हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें टीम में मौका नहीं मिला था और बाद में अचानक कॉल आया।

### वर्ल्ड कप में सिराज और कुलदीप का प्रदर्शन

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मोहम्मद सिराज को सिर्फ एक मैच खेलने का मौका मिला। USA के खिलाफ खेले गए उस मुकाबले में सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 29 रन देकर 3 विकेट झटके थे। वहीं, स्पिनर कुलदीप यादव ने भी टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेला, जो चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ था। उस मुकाबले में उन्होंने 1 विकेट हासिल किया था।

भले ही ये दोनों खिलाड़ी नियमित रूप से प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन टीम के लिए उनकी मौजूदगी और सपोर्ट ने ड्रेसिंग रूम का माहौल सकारात्मक बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाई।

# 'द हंड्रेड' में भारतीय महिला क्रिकेटर छायी रहीं

लंदन । इंग्लैंड में 'द हंड्रेड' महिला क्रिकेट लीग के लिए हुई नीलामी में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा सहित कई भारतीय महिला क्रिकेटर छायी रहीं। वहीं किसी भी फ्रेंचाइजी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली नहीं लगायी। इस लीग में नीलामी के लिए पाक की बाएं हाथ की बल्लेबाज मुनीबा अली, तेज गेंदबाज डायना बेग, लेफ्ट-आर्म स्पिनर सादिया इकबाल और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने अपना नाम दर्ज कराया था। इन चारों ही पाक क्रिकेटरों ने 15000 पाउंड के आधारमूल्य के साथ ही अपना नाम नीलामी में दर्ज कराया था। इस चारों में से केवल फातिमा सना और सादिया ही फाइनल नीलामी तक पहुंची थीं। वहीं इससे पहले कहा जा रहा था कि आईपीएल मालिकों वाली 'द हंड्रेड' टीमें शायद ही पाक खिलाड़ियों को शामिल करेंगी। इसके बाद इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने कहा था कि किसी भी देश के खिलाड़ियों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही कहा था कि चयन केवल प्रदर्शन, उपलब्धता और टीम की जरूरत को देखकर किया जाएगा।

# हार्दिक को पीठ पर तिरंगा बांधकर जश्न मनाना भारी पड़ा, वकील ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करायी

पुणे । भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को टी20 विश्वकप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत के बाद अपनी गर्लफ्रेंड महिका शर्मा के साथ जश्न मानना भारी पड़ है। हार्दिक जश्न के दौरान पीठ पर तिरंगा झंडा बांधे हुए थे और महिका के साथ अलग-अलग अंदाज में पोज दे रहे थे। इसी को लेकर एक वकील ने वाजिद खान ने पंड्या के खिलाफ राष्ट्रध्वज की गरिमा को ठेस पहुंचाने की शिकायल दर्ज करायी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में भारतीय टीम की जीत के बाद सभी खिलाड़ी खुशी मना रहे थे। इस दौरान सभी तस्वीरें भी खिंचा रहे थे। इसी दौरान हार्दिक और उनकी गर्लफ्रेंड महिका की हरकतों पर शिकायतकर्ता वकील ने आपति जतायी है। उनका कहना है कि पंड्या जश्न मनाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहे थे जबकि उनकी पीठ पर राष्ट्रीय ध्वज बंधा हुआ था। वहीं राष्ट्रीय ध्वज अधिनियम के अनुसार, हमें राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का सम्मान करना चाहिए पर हार्दिक अपनी जीत के जश्न में इतने डूब गये थे कि वे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ राष्ट्रीय ध्वज बांधकर मैदान में लेटे नजर आये। जो राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है। गौरतब है कि वाजिद के अलावा कई और लोगों ने भी हार्दिक और महिका की हरकतों को देखते हुए सोशल मीडिया पर इन दोनो को फटकारा है। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार महिका के कारण ही हार्दिक पंड्या और उनके बड़े भाई क्रुणाल पंड्या के बीच मतभेद पैदा हो गये हैं। इसी कारण क्रुणाल न तो फाइनल देखने स्टेडियम पहुंचे थे और न ही उन्होंने उन्हें सोशल मीडिया पर ही बधाई दी। हार्दिक का अपनी पहली पत्नी और सर्बियाई मॉडल नताशा स्टानकोविक से तलाक को गया है। उसके बाद महिका उनकी जिंदगी में आयीं।

# विश्व कप में जगह बनाने के बाद भारतीय महिला टीम की नजरें एफआईएच क्वालीफायर जीतने पर

**हैदराबाद (एजेंसी)।** विश्व कप के लिये क्वालीफाई कर चुकी भारतीय महिला हॉकी टीम की नजरें अब एफआईएच विश्व कप क्वालीफायर जीतने पर लगी है और इसके लिये शुक्रवार को इटली के खिलाफ सेमीफाइनल जीतना पहला कदम होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम पूल बी में तीन मैचों में सात अंक लेकर शीर्ष पर रही। स्कॉटलैंड के भी सात अंक थे लेकिन गोल औसत में पिछड़ने के कारण वह दूसरे स्थान पर है।

भारत ने पूल चरण में दो मैच जीते और एक ड्रॉ खेला। इटली पूल ए में दूसरे स्थान पर रही जिसने एक मैच जीता, एक ड्रॉ खेला और एक गंवाया। भारत के लिए फॉरवर्ड नवनीत कौर ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है जो अब तक चार गोल कर चुकी हैं। उन्होंने वेल्स के खिलाफ आखिरी पूल मैच में हैट्रिक लगाई

थी। इटली की उम्मीदें फेडरिका कार्टा पर टिकी होंगी जो अब तक तीन गोल कर चुकी है। कागजों पर भारत का पलड़ा भारी लग रहा है।

आमने सामने के मुकाबलों में दोनों टीमें 2012 से अब तक एक दूसरे के खिलाफ सात बार खेली हैं जिनमें से पांच भारत ने जीते, एक इटली ने और एक मैच ड्रॉ रहा। भारत के मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा, 'एफआईएच हॉकी महिला विश्व कप 2026 में जगह बनाना इस टीम के लिये बड़ी उपलब्धि है। खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह काबिले तारीफ है।'

उन्होंने कहा, 'हम यहां सिर्फ क्वालीफाई करने नहीं आए हैं। हम मैच दर मैच प्रदर्शन में सुधार करके टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। सेमीफाइनल एक और बड़ी चुनौती है और हम पूरे फोकस के साथ खेलेंगे।' मारिन ने कहा, 'इटली काफी प्रतिस्पर्धी टीम है और मजबूत टीमों को चुनौती देने में सक्षम है। हमारा फोकस रणनीति पर अमल पर रहेगा और इसी ऊर्जा तथा आत्मविश्वास के साथ खेलना चाहेंगे।' एफआईएच महिला और पुरूष विश्व कप नीदरलैंड और बेल्जियम में 15 से 30 अगस्त तक खेला जाएगा।

# जैक ड्रेपर ने पांच बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराया, क्वार्टर फाइनल में पहुंचें

इंडियन वेल्स (अमेरिका) (एजेंसी)। मौजूदा चैंपियन जैक ड्रेपर ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करके बीएनपी पारिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के चौथे दौर में पांच बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को 4-6, 6-4, 7-6 (5) से हराया। हाथ की चोट के कारण आठ महीने तक बाहर रहने के बाद वापसी करने वाले 24 वर्षीय ड्रेपर इस जीत से क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं जहां उनका मुकाबला दानिल मेदवेदेव से होगा। मेदवेदेव ने एक अन्य मैच में एलेक्स मिशेलसन को 6-2, 6-4 से पराजित किया। तीसरे सेट में जोकोविच 6-5 से आगे थे, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और ड्रेपर ने वापसी करते हुए मैच को टाईब्रेकर तक पहुंचा दिया। ड्रेपर ने मैच के बाद कहा, 'मुझे अब भी ऐसा नहीं लगता कि मैं उस तरह से खेल रहा हूं जैसा मैं खेलना चाहता हूं। लेकिन मैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रतिबद्ध हूं।' रिकॉर्ड 24 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन 38 वर्षीय जोकोविच ने 2008, 2011, 2014, 2015 और 2016 में इंडियन वेल्स में खिताब जीता था। जोकोविच इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में अपना 11वां खिताब जीतने के करीब पहुंच गए थे, लेकिन फाइनल में कार्लोस अल्काराज़ से हार गए थे।

# आईपीएल में शामिल होने विदेशी खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं रहेगा भारत पहुंचना

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के पहले चरण का कार्यक्रम तो घोषित कर दिया है पर उसके लिए टूर्नामेंट का आयोजन काफी कठिन हो सकता है। इसका कारण ये है कि मध्यपूर्व में जारी युद्ध के कारण कई देशों के खिलाड़ियों के लिए आईपीएल टीमों से जुड़ना कठिन हो जाएगा। अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए हमले का असर अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा पर पड़ा है जिससे दोहा और दुबई एयरपोर्ट से कई उड़ानें बाधित हुई हैं। इसी कारण दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम के कुछ खिलाड़ी टी20 विश्व कप के बाद भी भारत में फंसे रहे थे। ऐसे में अब आईपीएल की सभी टीमों में शामिल इन देशों के खिलाड़ियों के लिए भारत आना आसान नहीं होगा। बोर्ड के एक अधिकारी ने भी माना है कि उन्हें समय पर वापस भारत लाना मुश्किल काम होगा। साथ ही कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से हवाई किराए काफी बढ़ गए हैं। पहला मैच जहां आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद। वहीं दूसरा मैच मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच वानखेड़े स्टेडियम में होगा. बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, सत्र के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बेंगलुरु में पांच और रायपुर में दो घरेलू मैच खेलेगी। पंजाब किंग्स की टीम न्यू चंडीगढ़ में चार और धर्मशाला में तीन घरेलू मैच खेलेगी जबकि राजस्थान रॉयल्स गुवाहाटी में तीन और जयपुर में चार घरेलू मैच खेलेगी। बीसीसीआई ने कहा, इस दौरान (पहले 16 दिन) टूर्नामेंट में चार ही डबल-हेडर होंगे।

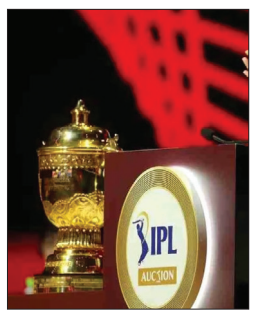

# युवराज सिंह को टीम से बाहर करने में एमएस धोनी का हाथ था? पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने बता दिया सच

**मुम्बई (एजेंसी)।** पूर्व भारतीय क्रिकेटर और चयनकर्ता संदीप पाटिल ने एक लंबे समय से चल रहे विवाद पर खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महेन्द्र सिंह धोनी का युवराज सिंह को भारतीय टीम से बाहर करने के फैसले में कभी कोई हाथ नहीं था। पाटिल ने बताया कि अपने चयनकर्ता कार्यकाल के दौरान उन्होंने कभी भी धोनी को युवराज को ड्रॉप करने की मांग करते नहीं सुना। उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब युवराज के पिता लगातार धोनी पर आरोप लगाते रहे हैं।

### चयन बैठकों में कभी नहीं उठी ऐसी मांग

संदीप पाटिल ने एक इंटरव्यू में कहा कि चयन समिति की बैठकों, विदेशी दौरों या मैचों के दौरान कभी भी धोनी ने युवराज सिंह को टीम से बाहर करने की बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि वह इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ रिकॉर्ड पर कह सकते हैं कि धोनी ने ऐसा कोई सुझाव या दबाव नहीं बनाया। पाटिल के अनुसार, धोनी का चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का स्वभाव भी नहीं था और वह चयन समिति के फैसलों का सम्मान करते थे।

### धोनी को था चयन समिति पर पूरा भरोसा

पाटिल ने आगे कहा कि धोनी हमेशा चयनकर्ताओं के निर्णयों का सम्मान करते थे। उन्होंने बताया कि टीम के कप्तान के तौर पर धोनी को चयन समिति की कार्यप्रणाली पर पूरा भरोसा था और वह आमतौर पर टीम चयन के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे। इस बयान से यह साफ संकेत मिलता है कि युवराज सिंह को टीम से बाहर करने का फैसला चयनकर्ताओं की रणनीति और उस समय के प्रदर्शन के आधार पर लिया गया होगा।

### योगराज सिंह लगातार लगाते रहे हैं आरोप

दूसरी ओर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह कई बार सार्वजनिक रूप से धोनी को अपने बेटे के करियर में गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। योगराज ने कई इंटरव्यू में यह कहा कि धोनी के कारण ही युवराज को टीम से बाहर किया गया। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस मामले में धोनी को कभी माफ नहीं करेंगे।

एक इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा था कि धोनी ने उनके बेटे के साथ गलत किया और इससे युवराज का करियर प्रभावित हुआ। उन्होंने यहां तक कहा कि युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी फिर से देखने को शायद ही मिले और वह चार-पांच साल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते थे। उनके इस बयान ने क्रिकेट जगत में काफी चर्चा पैदा की थी।

### पाटिल ने कहा - पिता का भावुक होना स्वाभाविक

संदीप पाटिल ने योगराज सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक पिता का अपने

बेटे के लिए भावुक होना बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में आरोप गलत व्यक्ति पर लगाए जा रहे हैं। पाटिल के अनुसार, चयन प्रक्रिया कई पहलुओं को ध्यान में रखकर होती है और किसी एक व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है।

# भविष्य में सैमसन को बनाया जा सकता है भारतीय टी20 टीम का कप्तान : कैफ

मुम्बई । सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम के टी20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद अब सवाल उठाता है कि उनके बाद किसे कप्तानी दी जानी चाहिये। इसी को लेकर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा है विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भविष्य में कप्तानी दी जा सकती है क्योंकि उन्हें घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में कप्तानी का लंबा अनुभव है। कैफ के अनुसार सैमसन के पास वह अनुभव और मानसिक ठहराव है, जो किस कप्तान के पास होना जरुरी है। उन्होंने कहा, संजू ही कप्तान बन सकते हैं उसमें सभी योग्यताएं हैं। मेरा मानना है कि कप्तान वही अच्छा होता है जिसने दुनिया देखी हुई है। कैफ के अनुसार, किसी नए खिलाड़ी को सीधे कप्तानी सौंपना नुकसानदे हो सकता है, क्योंकि उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कठिन हालातों का सामना नहीं किया होता है। कप्तानी के लिए कैफ ने आईपीएल के अनुभव को अहम बताया है। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करने से पहले खिलाड़ी को आईपीएल जैसे बड़े मंच पर अपने को एक लीडर के रूप में साबित करना चाहिए। सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से ऐसा किया है। उन्होंने कहा, कप्तान उसी को बनना चाहिए जिसने ट्रॉफी जिताई हो जिसने कप्तानी पहले करी हो जिसने आईपीएल में 100 150 मैच खेले हो। कैफ ने कहा कि संजू राजस्थान रॉयल्स को कप्तानी करते हुए फाइनल तक ले गये। । इस लंबे अनुभव की वजह से उन्हें मैदान पर गेंदबाजी बदलाव करने और दबाव के क्षणों में किसी प्रकार सही फैसले लेते हैं ये पता है। कैफ ने सैमसन की तुलना वर्तमान और पूर्व कप्तानों से करते हुए परिपक्वता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा भी 30-32 साल की उम्र में भारतीय टीम के कप्तान बने थे, जब वे आईपीएल में पांच ट्रॉफियां जीतकर एक परिपक्व कप्तान बन गये थे।

## संक्षिप्त समाचार

### पश्चिम एशिया तनाव : पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर की बात

**मास्को, एजेंसी।** पश्चिम एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच रूस ने हालात को शांत करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से फोन पर बातचीत कर जल्द से जल्द तनाव कम करने की अपील की। रूस ने साफ कहा कि मौजूदा संकट का समाधान सैन्य टकराव नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक बातचीत से ही संभव है। रूस की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक यह बातचीत ऐसे समय हुई जब अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच जवाबी हमलों का दौर जारी है। खाड़ी क्षेत्र के कई देशों तक इस तनाव का असर पहुंच चुका है। ऐसे में रूस ने सभी पक्षों से संयम बरतने और हालात को बिगड़ने से रोकने की जरूरत बताई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष को जल्द कम किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि रूस का रुख शुरू से ही यही रहा है कि विवादों को राजनीतिक और कूटनीतिक रास्ते से सुलझाया जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी रूस के समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और मानवीय सहायता देने के लिए आभार जताया। पश्चिम एशिया के खाड़ी देशों में रूस के बड़े रणनीतिक और आर्थिक हित हैं। इसी वजह से मॉस्को लगातार इस संकट को कम करने की कोशिश कर रहा है। रूस ने अमेरिका, ईरान और क्षेत्र के अन्य देशों से संपर्क बनाकर हालात को संभालने का प्रयास शुरू किया है ताकि युद्ध जैसी स्थिति बनने से पहले समाधान निकल सके। सोमवार रात मौजूदा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पुतिन से फोन पर बात की। करीब एक घंटे चली इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति के साथ रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भी चर्चा हुई। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि पुतिन ने ईरान संकट को लेकर ट्रंप के सामने क्या प्रस्ताव रखा। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि शुरुआत से ही पुतिन ने तनाव कम करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की थी। लेकिन फिलहाल हालात ऐसे हैं कि किसी भी समाधान के लिए कई देशों के बीच सहमति बनना जरूरी है। रूस ने कहा कि वह कूटनीतिक बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को साथ आना होगा।

### स्विट्जरलैंड में बर्न के पास बस में लगी आग, छह लोगों की मौत; तीन गंभीर रूप से घायल

**बर्न, एजेंसी।** स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न के पास एक दर्दनाक हादसे में क्षेत्रीय बस में आग लगने से कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा मंगलवार शाम बर्न से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिम स्थित केरजर्स कस्बे में हुआ। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस उसकी चपेट में आ गई। फ्रिबर्ग कैंटन के पुलिस प्रवक्ता फ्रेडरिक पापो ने बताया कि शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे किसी स्वैच्छिक कृत्य की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। क्षेत्रीय सरकार ने एक बयान में कहा कि जब बचाव दल मौके पर पहुंचे तो बस पूरी तरह आग की लपटों में घिरी हुई थी और अंदर मौजूद लोगों को बचाना बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस के अनुसार, हादसे में गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके अलावा दो अन्य लोगों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। जिस बस में आग लगी वह पोस्टबस द्वारा संचालित क्षेत्रीय परिवहन बस थी। यह कंपनी स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय डाक सेवा से संबद्ध है और कई क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं देती है। पुलिस और जांच एजेंसियां फिलहाल घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि बस में आग कैसे लगी और इसके पीछे किसी की साजिश है या नहीं, यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

### लंदन : होली उत्सव पर हमला ब्रिटिश संसद में गूंजा मुद्दा

**लंदन, एजेंसी।** उत्तर-पश्चिम लंदन के हैरो में होली मना रहे हिंदू समुदाय पर उपद्रवियों ने हमला किया है। कुछ लोगों ने लाउडस्पीकर तोड़े और लोगों पर हमला किया। ब्रिटिश सरकार ने घटना की कड़ी निंदा की है। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने संसद में इस मुद्दे को उठाते हुए बताया कि उपद्रवियों ने लाउडस्पीकर तोड़कर उत्सव में खलल डाला। इस पर लीडर ऑफ द कॉमन्स एलन कैंपबेल ने दुख जताते हुए कहा कि धार्मिक घृणा किसी भी रूप में घृणित है और हमारे समाज में इसका कोई स्थान नहीं है। एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है।

# व्हाइट हाउस ने चुनाव सुधार विधेयक को आगे बढ़ाया



**वॉशिंगटन, एजेंसी।** व्हाइट हाउस ने कांग्रेस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित व्यापक चुनाव सुधारों को पारित करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि यह कानून मतदान की अखंडता को मजबूत करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि केवल अमेरिकी नागरिक ही अमेरिकी चुनावों में भाग लें।

व्हाइट हाउस की एक ब्रीफिंग में प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने प्रस्तावित सेव अमेरिका एक्ट को 'हमारे राष्ट्र के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विधायी प्रस्तावों में से एक' बताया। लेविट ने कहा, 'सेव अमेरिका एक्ट सभी अमेरिकियों के बीच बेहद लोकप्रिय है क्योंकि इसकी हर धारा सामान्य समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस कानून में राष्ट्रपति द्वारा मांगे गए पांच प्रमुख प्रावधान शामिल हैं। 'सेव अमेरिका एक्ट' में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के अनुरोध के अनुसार पांच सरल आवश्यकताएं हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार, पहला प्रावधान मतदाताओं को मतदान से पहले पहचान पत्र दिखाने की आवश्यकता करेगा। लेविट ने कहा, 'नंबर एक, अमेरिकी चुनाव में मतदान करने के लिए मतदाताओं को पहचान पत्र दिखाना होगा। उन्होंने कहा कि मतदाता पहचान के लिए जनसमर्थन दलगत सीमाओं से परे मजबूत है। 'नब्बे प्रतिशत अमेरिकी, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक डेमोक्रेटिक मतदाता भी शामिल हैं, इससे सहमत हैं।' दूसरी आवश्यकता मतदाता पंजीकरण के समय नागरिकता का प्रमाण प्रस्तुत करने की होगी। उन्होंने कहा, 'सेव अमेरिका एक्ट के तहत सभी मतदाताओं को अमेरिकी चुनावों में वोट देने के लिए पंजीकरण कराने हेतु नागरिकता का प्रमाण दिखाना होगा।' लेविट ने तर्क देते हुए कहा कि हाल के वर्षों में अवैध आव्रजन में वृद्धि के कारण यह कदम आवश्यक है। 'केवल अमेरिकी नागरिकों को ही अमेरिकी चुनावों में वोट देने का अधिकार है।' 'हालांकि जब जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स ने अमेरिका में करोड़ों अवैध विदेशियों को आने की अनुमति दी, तो अब पहले से कहीं अधिक ज़रूरी हो गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हमारे देश की मतदाता सूची में केवल अमेरिकी नागरिक ही पंजीकरण करा रहे हों और कांग्रेस को इसे पारित करना चाहिए।' एक अन्य प्रावधान सार्वभौमिक मेल-इन बैलेट को समाप्त करेगा जबकि सीमित अपवाद बनाए रखेगा। उन्होंने कहा, 'सेव अमेरिका एक्ट सार्वभौमिक मेल-इन बैलेट की बेहद असुरक्षित प्रथा को समाप्त करता है।' साथ ही, उन्होंने कहा कि कुछ श्रेणियों के मतदाताओं को अब भी डाक के माध्यम से मतदान की अनुमति होगी। 'सेव अमेरिका एक्ट बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा जैसे कारणों के लिए अमेरिकियों को मेल-इन बैलेट का उपयोग करने के अपवाद बनाए रखता है।' लेविट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पूर्व विदेश मंत्री जेम्स बेकर की अध्यक्षता वाले द्विदलीय चुनाव सुधार आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'संघीय चुनाव सुधार आयोग की 2005 की द्विदलीय रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला था कि अनुपस्थित बैलेट संभावित मतदाता धोखाधड़ी का सबसे बड़ा स्रोत बने रहते हैं।' प्रस्तावित कानून में चुनाव प्रक्रिया से परे अन्य मुद्दों को संबोधित करने वाले प्रावधान भी शामिल हैं। लेविट ने कहा, 'सेव अमेरिका एक्ट पुरुषों को महिलाओं के खेलों में प्रतिस्पर्धा करने से स्थायी रूप से प्रतिबंधित करता है।' उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह विधेयक नाबालिगों के लिए लिंग-संबंधी चिकित्सीय प्रक्रियाओं पर भी रोक लगाएगा। 'नंबर पांच, सेव अमेरिका एक्ट बच्चों के लिए ट्रांसजेंडर म्यूटिलेशन सर्जरी पर प्रतिबंध लगाता है।' लेविट ने दोनों दलों के सांसदों से इस कानून का समर्थन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'सेव अमेरिका एक्ट को पारित करना चुनावी ईमानदारी को मजबूत करने और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम है।' व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति चाहते हैं कि कांग्रेस इस कदम पर तेजी से कार्रवाई करे। 'राष्ट्रपति कांग्रेस से इस काम को पूरा करने और इस ऐतिहासिक विधेयक को तुरंत उनके हस्ताक्षर के लिए उनकी मेज तक भेजने का आह्वान कर रहे हैं।' हाल के वर्षों में अमेरिका में चुनावी कानून सबसे विवादास्पद राजनीतिक मुद्दों में से एक बन गए हैं, विशेष रूप से 2020 के अत्यधिक ध्रुवीकृत राष्ट्रपति चुनाव के बाद। रिपब्लिकन नेताओं ने बार-बार कड़े मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन की आवश्यकताओं की वकालत की है, जबकि कई डेमोक्रेट्स का तर्क है कि ऐसे कदम कुछ मतदाता समूहों के लिए मतदान को अधिक कठिन बना सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कई अमेरिकी राज्यों में मतदान नियमों पर बहस तेज हो गई है, जहाँ विधानसभाओं ने मतदाता पहचान, मेल-इन बैलेट और चुनाव प्रशासन को प्रभावित करने वाले कई बदलाव पेश किए हैं, क्योंकि दोनों दल भविष्य के राष्ट्रीय चुनावों की तैयारी कर रहे हैं।

# भारत से सटी सीमा पर सड़क नेटवर्क मजबूत करने में जुटा चीन, 394 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनाएगा ड्रैगन



**बीजिंग, एजेंसी।** चीन अपनी 15वीं पंचवर्षीय योजना के तहत अगले पांच वर्षों में भारत से सटे संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करने की योजना पर काम कर रहा है। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 15वीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि एक परियोजना के तहत शिनजियांग, उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में स्थित दुर्गम तियानशेन पर्वत श्रृंखला के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने के लिए 394 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा।

**योजना को मंजूरी के लिए एनपीसी के पास भेजा गया**

यह पंचवर्षीय योजना चीन की राष्ट्रीय विधायिका, राष्ट्रीय जन कांग्रेस (एनपीसी) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई है। इसका सत्र अभी चल रहा है। यह मार्ग विवादित अक्साई चिन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एक रणनीतिक सड़क के समानांतर बनेगा, जिसका निर्माण 1962 के भारत-चीन सीमा युद्ध के बाद सैन्य गतिशीलता को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। मध्य शिनजियांग में दुशांजी-कुका राजमार्ग का निर्माण 2032 तक पूरा होने की उम्मीद है।

**तिब्बत जाने वाले राजमार्गों को भी बेहतर करेगा चीन :** इस पंचवर्षीय योजना में तिब्बत की ओर जाने वाले तीन मौजूदा राजमार्गों के उन्नयन का भी प्रस्ताव है। चीन के भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाने वाली 15वीं पंचवर्षीय योजना में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ई-वाहनों और बैटरी जैसी नई उत्पादक शक्तियों पर खासा जोर दिया गया है ताकि कमजोर पड़ रही अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। इस पंचवर्षीय योजना को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

**चीन की कई योजनाओं से भारत में बढ़ी चिंता :** एनपीसी को कम्युनिस्ट पार्टी का रबर-स्टांप संसद माना जाता है और वह अपने मौजूदा सत्र में इस योजना को मंजूरी देने वाली है। चीन ने पिछले साल 14वीं पंचवर्षीय योजना पूरी की है, जिसके दौरान उसने भारतीय सीमा के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े बांध का निर्माण शुरू किया। पिछली जुलाई में चीन ने 170 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से इस बांध का निर्माण शुरू किया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना बताया जा रहा है। इसके तहत भारी मात्रा में पानी जमा करने की क्षमता और नदी के प्रवाह में बदलाव को लेकर भारत और बांग्लादेश जैसे तटीय देशों में चिंताएं पैदा हो गई हैं।

# बांग्लादेश किसी के कहने पर नहीं चलेगा: विदेश मंत्री खलीलुर रहमान

**ढाका , एजेंसी।** बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा है कि अब उनका देश किसी के कहने पर नहीं चलेगा और अपनी मर्जी से काम करेगा। उन्होंने यह टिप्पणी लंदन में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ब्रिटेन यूनिट की इफ्तार पार्टी के दौरान कही। वे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। उन्हें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरपर्सन तारिक रहमान के बयान का जिक्र किया और कहा कि बांग्लादेश सबके साथ है। ब्रिटेन के दौरे पर पहुंचे खलीलुर रहमान ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर हमला बोला और उनके कार्यकाल को फासिस्ट शासन कहकर संबोधित किया। बांग्लादेश के मीडिया आउटलेट प्रथम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा कि फासीवादी शासन के दौरान देश की विदेश नीति दूसरे देश के हाथों गिरवी रख दी गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उस समय विदेश नीति बनाने के लिए कुछ कास नहीं किया गया। हालांकि, रहमान ने भारत का नाम नहीं लिया लेकिन उनके बयान को शेख हसीना के दौरा में ढाका और नई दिल्ली के नजदीकी संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है।इफ्तार पार्टी में बोलते हुए खलीलुर रहमान ने देश की आजादी, संप्रमभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राष्ट्रीय हित और सम्मान को बांग्लादेश की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने इस विदेश नीति को लागू किया था और देश अब उसी तरफ लौट रहा है। शहीद राष्ट्रपति जियाउर रहमान के समय में ये सिद्धांत बांग्लादेश की विदेश नीति की खासियत थे। मैं उस समय विदेश मंत्रालय में शामिल हुआ था। यह हमारी विदेश नीति का स्वर्ण काल था। अब हम उस पोजीशन पर लौट रहे हैं। बांग्लादेश में हालिया चुनाव में बंपर जीत हासिल करने के बाद तारिक रहमान ने खलीलुर रहमान को अपना विदेश मंत्री बनाया था। विदेश मंत्री के रूप में खलीलुर रहमान की तैनाती बांग्लादेश के राजनीतिक हलके के लिए चौंकाने वाली थी।

# ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने की छूट : व्हाइट हाउस

**वाशिंगटन, एजेंसी।** व्हाइट हाउस ने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहे यूएस मिलिट्री कैंपेन से पैदा हुई दिक्कतों के बीच ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने की एक बड़ी कोशिश के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए तत्कालीन छूट को मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि यह फैसला प्रेसिडेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और नेशनल सिक्योरिटी टीम के सदस्यों के बीच बातचीत के बाद लिया गया। लेविट ने एक सवाल के जवाब में रिपोर्टर्स से कहा, 'प्रेसिडेंट और ट्रेजरी सेक्रेटरी और पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम इस फैसले पर इसलिए पहुंची क्योंकि भारत में हमारे सहयोगी अच्छे रहे हैं और उन्होंने पहले भी रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह तत्कालीन उपाय ईरान



के संकट से पैदा हुई ग्लोबल तेल सप्लाई में रुकावटों को दूर करने के लिए था। लेविट ने आगे कहा, 'जब हम ईरानियों की वजह से दुनिया भर में तेल सप्लाई के इस 'टेम्पररी गैप' को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हें तत्कालीन तौर पर रूसी तेल लेने की इजाजत दे दी है।' लेविट ने बताया कि छूट मिलने से पहले ही शिपमेंट भेज दिए गए थे। व्हाइट हाउस के मुताबिक, प्रशासन को उम्मीद नहीं है कि इस व्यवस्था से मॉस्को को आर्थिक रूप से कोई खास फायदा होगा। यह बात तब आई जब व्हाइट हाउस ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' पर अपडेट दिया, जो ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवल क्षमता को टारगेट करने वाला यूएस मिलिट्री कैंपेन है। लेविट ने कहा कि दस दिन पहले शुरू होने के बाद से ऑपरेशन में तेजी से प्रोग्रेस हुई है। अब तक 5,000 से ज्यादा दुश्मन के ठिकानों पर हमला किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान की जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता में तेजी से गिरावट आई है। 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' शुरू होने के बाद से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले 90 प्रतिशत से ज्यादा कम हो गए हैं, और उनके ड्रोन हमले लगभग 35 प्रतिशत कम हो गए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के नेवल एसेट्स को भी निशाना बनाया है। लेविट ने कहा, 'हमने 50 से ज्यादा ईरानी नेवल वेसल को नष्ट कर दिया है, जिसमें एक बड़ा ड्रोन कैरियर शिप भी शामिल है। ईरानी नेवी को 'लड़ाई में बेअसर' माना गया है। लेविट ने कहा, ''ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के बताए गए मकसद वही हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करना, उनकी ईरानी मिसाइल इंडस्ट्री को जमीन पर गिराना, यह पक्का करना कि उनके आतंकवादी प्रॉक्सी अब इस इलाके को अस्थिर न कर सकें, और यह पक्का करना कि ईरान को कभी न्यूक्लियर वेपन न मिले।'

व्हाइट हाउस ने इस बात पर भी जिक्र किया कि यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया के सबसे जरूरी तेल शिपिंग रूट्स में से एक, होर्मुज स्ट्रेट के जरिए एनर्जी का लगातार फ्लो पक्का करेगा। लेविट ने कहा कि ट्रंप ने एनर्जी सप्लाई रूट्स की सुरक्षा के लिए अपना वादा दोहराया है।

# पत्नी की हत्या कर फरार हुआ भारतीय, एफबीआई ने इनाम बढ़ाकर किया नौ करोड़ रुपये

**वाशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) ने 2015 में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में फरार भारतीय नागरिक भद्रेश कुमार चेतनभाई पटेल की गिरफ्तारी के लिए इनाम की राशि बढ़ाकर 10 लाख डॉलर (करीब नौ करोड़ रुपये) कर दी है। इससे पहले इस मामले में सूचना देने पर 2.5 लाख डॉलर तक का इनाम घोषित था। 35 वर्षीय भद्रेश कुमार पटेल को एफबीआई की टेन मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स सूची में शामिल किया गया है। एजेंसी का मानना है कि वह अभी भी फरार है और बेहद खतरनाक हो सकता है। डोनट शॉप में हुई थी पत्नी की हत्या जांच एजेंसियों के अनुसार यह घटना 12 अप्रैल 2015 को अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के हैनोवर शहर में हुई थी। उस समय पटेल और उनकी पत्नी पलाक पटेल एक डोनट शॉप में काम करते थे। आरोप है कि देर रात काम के दौरान पटेल ने दुकान के पिछले कमरे में अपनी 21 वर्षीय पत्नी पर किसी भारी वस्तु से कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद ऐसे फरार हुआ आरोपी एफबीआई के मुताबिक हत्या के बाद पटेल दुकान के पिछले दरवाजे से फरार हो गया। इसके बाद वह सड़क पार कर उस अपार्टमेंट में गया, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। वहां से उसने कुछ सामान और नकदी ली और फिर टैक्सी लेकर न्यू जर्सी के न्यूर्क इलाके पहुंच गया। रिपोर्ट के अनुसार वह न्यूर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक होटल में तड़के करीब 3 बजे चेक-इन किया। उसके पास कोई सामान नहीं था और वह सिर्फ पहने हुए कपड़ों में ही होटल पहुंचा था। सुबह करीब 10 बजे उसने होटल से चेक-आउट किया और शटल बस से न्यूर्क पेन स्टेशन पहुंचा। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला है।

**हथियारबंद और बेहद खतरनाक माना जा रहा :** एफबीआई ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि पटेल को हथियारबंद और बेहद खतरनाक माना जाना चाहिए। इसलिए आम लोगों से सावधानी बरतने और किसी भी जानकारी को तुरंत एजेंसियों तक पहुंचाने की अपील की गई है।

**हत्या के पीछे यह वजह हो सकती है :** जांचकर्ताओं का मानना है कि हत्या के पीछे भारत लौटने को लेकर दंपत्ति के बीच विवाद हो सकता है। बताया गया कि उस समय दोनों के वीजा की अवधि खत्म हो चुकी थी और पलाक भारत लौटना चाहती थीं, जबकि पटेल इसके खिलाफ था। एफबीआई के विशेष एजेंट जोनाथन शेफर के अनुसार, आरोपी को शायद डर था कि अगर उसकी पत्नी भारत लौट गई तो उसे सामाजिक रूप से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।

# हॉर्मुज के आस-पास संकट गहराया: अमेरिका ने तबाह किए ईरान के 16 माइन बिछाने वाले जहाज

**वाशिंगटन, एजेंसी।** पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने ईरान के खिलाफ समुद्र में बड़ी सैन्य कार्रवाई का दावा किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार, हॉर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान की कई नौकाओं को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया गया, जिनका इस्तेमाल समुद्र में बारूदी सुरंगें (नैवल माइन) बिछाने के लिए किया जा सकता था।

अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च को अमेरिकी बलों ने ईरान की कई नौसैनिक नौकाओं पर हमला किया, जिनमें 16 माइन बिछाने वाली नावें शामिल थीं। कमांड ने इस कार्रवाई का एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें समुद्र में किए गए हमलों के दृश्य दिखाई देते हैं।

**ईरान को दी सख्त चेतावनी :** ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हॉर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी तरह की समुद्री माइन बिछाई गई हैं तो उन्हें तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो अमेरिका की सैन्य प्रतिक्रिया बेहद कठोर हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान संभावित रूप से लगाए गए विस्फोटकों को हटा देता है तो इससे क्षेत्र में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जाएगा।

**खुफिया रिपोर्ट में माइन बिछाने की आशंका :** अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि ईरान इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग में समुद्री बारूदी सुरंगें तैनात करने



की तैयारी कर रहा है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि संभव है कि सीमित संख्या में माइन पहले ही पानी में डाली जा चुकी हों।

**दुनिया के लिए बेहद अहम है हॉर्मुज जलडमरूमध्य :** हॉर्मुज जलडमरूमध्य ईरान और ओमान के बीच स्थित दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर कारोबार होने वाले कुल तेल का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का सैन्य तनाव वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर बड़ा असर डाल सकता है।

**जहाजों के लिए बढ़ा जोखिम :** पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बाद से विशेषज्ञों ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य को व्यावसायिक जहाजों के लिए उच्च जोखिम वाला क्षेत्र बताया है। ईरान की नौसेना और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव आने वाले दिनों में वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है।

# ईरान युद्ध से वैश्विक स्तर पर बढ़ सकती है उर्वरक की लागत

**वॉशिंगटन, एजेंसी।** अमेरिकी कृषि नेताओं ने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों को चेतावनी दी कि ईरान से जुड़े संघर्ष के कारण वैश्विक उर्वरक और ईंधन की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उन किसानों पर नया दबाव पड़ेगा जो पहले से ही बढ़ती लागत और अस्थिर बाजारों से जूझ रहे हैं।

चेतावनी उस समय दी गई जब सीनेट कृषि समिति की सुनवाई में अमेरिकी-उगाए गए कृषि उत्पादों की घरेलू मांग बढ़ाने पर चर्चा हो रही थी, जबकि किसान वित्तीय दबाव और अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। अमेरिकन फार्म ब्यूरो फेडरेशन के अध्यक्ष ज़िप्पी डुवॉल ने सीनेटरों से कहा कि भू-राजनीतिक तनाव से कृषि अर्थव्यवस्था और खराब होने की संभावना है। उन्होंने समिति के सामने गवाही में कहा, 'ईरान में संघर्ष से ईंधन और उर्वरक की लागत और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। कृषि नेताओं ने कहा कि कृषि क्षेत्र पहले से ही गिरती कमोडिटी कीमतों और ऊंची उत्पादन लागत के कारण गंभीर दबाव में है। नॉर्थ डकोटा फार्मर्स यूनियन के अध्यक्ष मैट परड्यू ने कहा कि किसान आर्थिक और भू-राजनीतिक चुनौतियों के संयोजन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'किसान महत्वपूर्ण आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, हमारी इनपुट लागत ऊँची है, कमोडिटी कीमतें कम हैं, और हमारे बाज़ार बेहद अस्थिर हैं।' उन्होंने कहा कि वैश्विक तनाव स्थिति को और खराब कर रहे हैं। परड्यू ने कानून निर्माताओं से कहा, 'व्यापार विवाद और अब ईरान में युद्ध ने इन आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है।'



परड्यू ने कहा कि भू-राजनीतिक तनाव कृषि अर्थव्यवस्था के दोनों पक्षों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'भू-राजनीतिक तनावों ने कृषि आय के समीकरण के दोनों पक्षों पर दबाव पैदा किया है, जिससे इनपुट लागत बढ़ रही है और कमोडिटी कीमतें दब रही हैं। सीनेट की सुनवाई ने किसानों के बीच बढ़ती उर्वरक लागत को लेकर चिंता को उजागर किया, जो गेहूं, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों के उत्पादन खर्च का बड़ा हिस्सा होती है। कानून निर्माताओं ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति मार्गों में बाधाएं इस समस्या को और गंभीर बना सकती हैं। सीनेटर टीना स्मिथ ने कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य में तनाव उर्वरक लागत को और बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा, 'आप जानते हैं कि अब हमारे पास अतिरिक्त भू-राजनीतिक तनाव हैं। होर्मुज़ जलडमरूमध्य और वहाँ की कुछ चुनौतियां, जो पहले से ही ऊँची उर्वरक लागत में एक और वृद्धि ला रही हैं।' स्मिथ ने चेतावनी दी कि लागत में यह वृद्धि खेती के संचालन को आर्थिक रूप से अस्थिर बना सकती है। उन्होंने कहा, 'गेहूं के एक एकड़ पर उर्वरक की लागत आपके उत्पादन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत होती है और अब यह 30 प्रतिशत और बढ़ रही है। कृषि नेताओं ने कहा कि किसान पहले से ही लाभ में बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्यक्ष जॉन बूज़मैन ने कहा कि अमेरिकी कृषि अर्थव्यवस्था गंभीर दबाव में है। बूज़मैन ने कहा, अगर आप जमीन में कुछ भी बो रहे हैं, तो संभवतः आप पैसा खो रहे हैं। उनके गृह राज्य अर्कांसस में इस समय कोई भी रो क्रॉप लाभदायक नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्ष पूरे देश के किसानों के लिए विशेष रूप से कठिन रहे हैं। बूज़मैन ने कहा, 'पिछले तीन साल बिल्कुल ही दंडात्मक रहे हैं।' बढ़ती लागत, व्यापार में व्यवधान और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने मिलकर कृषि आय को कमजोर कर दिया है। परड्यू ने चेतावनी दी कि किसान ऐतिहासिक रूप से उच्च कर्ज बोझ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, 'किसान और पशुपालक रिकॉर्ड स्तर के कर्ज का बोझ उठा रहे हैं, जो 1980 के दशक से भी अधिक है। डुवॉल ने कहा कि कृषि क्षेत्र को भू-राजनीतिक झटकों और व्यापार व्यवधानों के प्रति अपनी संवेदनशीलता कम करने के लिए घरेलू बाज़ारों को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा, 'आज हमें अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए घरेलू मांग को मजबूत करना होगा।' कृषि समूहों ने कानून निर्माताओं से कहा कि हालांकि सरकारी सहायता कार्यक्रमों ने किसानों को हाल की संकट स्थितियों से उबरने में मदद की है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान बाज़ारों के विस्तार और लागत को स्थिर करने पर केंद्रित होने चाहिए।


स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

## प्रधानमंत्री कहां हैं? एलपीजी की कमी पर ध्यान देने के बजाए वे चुनाव रैलियां कर रहे हैं- राउत

मुंबई (एजेंसी)। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने गुरुवार को केरल और तमिलनाडु में रैलियां करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और उनसे व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कमी पर ध्यान देने की मांग की। संजय राउत ने केंद्र सरकार से पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री कहां हैं? वे केरल और तमिलनाडु में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और वे अपने विरोधियों के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं। राउत ने कहा कि पीएम मोदी ईरान-इजराइल संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह स्थिति लोगों में भय पैदा कर रही है। होटल और रेस्तरां बंद हो रहे हैं। मोदी सरकार ने इस पर कुछ नहीं कहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश ऐसे नेतृत्व के हाथों में है। यह घटनाक्रम गुरुवार को केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी की जनसभाओं के बाद सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार भारतीयों के हितों को सर्वोपरि रखने के उसी दृष्टिकोण का पालन करेगी और घबराने या अफवाहों पर ध्यान देने की कोई जरुरत नहीं। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित है। हम इंडिया फर्स्ट की विचारधारा में विश्वास रखते हैं। बता दें पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर व्यावसायिक एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी हो गई है, जिसके बाद केंद्र ने घरेलू खपत को प्राथमिकता देते हुए जरुरी वस्तु अधिनियम लागू किया है।

## टल गया बड़ा संकट...कुकी समुदाय ने नागा समुदाय के सभी 21 नागरिकों बातचीत के बाद छोड़ा

इंफाल (एजेंसी)। मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी समुदाय के ग्रामीणों और सशस्त्र लोगों द्वारा हिरासत में लिए गए नागा समुदाय के सभी 21 नागरिकों को बातचीत के बाद छोड़ दिया गया। इंफाल पुलिस अधिकारी ने बताया कि उखरुल-इम्फाल मार्ग पर तीन वाहनों में यात्रा कर रहे तंगखुल नागा समुदाय के नागरिकों को शांगकाई में कुकी गांव वालों और हथियारबंद लोगों ने बंधक बनाया था। राज्य सरकार के अधिकारियों और नागा एवं कुकी समुदायों के नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के नेताओं के बीच गहन बातचीत और विचार-विमर्श के बाद सुबह बंधकों को रिहा किया गया। रिहाई के बाद नागरिकों को लिटान पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में उन्हें उनके परिवारों से मिला दिया गया। 21 लोगों को बंधक बनाने के कारण तंगखुल नागा बहुल उखरुल जिले में विशेष रूप से कुकी बहुल कांगपोकपी जिले से सटे इलाकों में तनाव बना रहा। सुरक्षा बलों ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए तलाशी और क्षेत्र नियंत्रण अभियान चलाए। इसके पहले मणिपुर में तंगखुल नागाओं की सर्वोच्च संस्था, तंगखुल नागा लोंग (कार्यकारी समिति) ने उखरुल जिले के कुकी-बहुल गांव शांगकाई में हिरासत में लिए गए 20 से अधिक नागा नागरिकों की सुरक्षित रिहाई की मांग करते हुए दो घंटे का अल्टीमेटम जारी किया था। तंगखुल मणिपुर की सबसे बड़ी नागा जनजाति है और मुख्य रूप से राज्य के पांच से छह जिलों में पाई जाती है।

## एलपीजी संकट पर कांग्रेस पर हमलावार कंगना.... जनता को गुमराह करने की साजिश

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में एलपीजी संकट को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रानोत ने विपक्ष के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधकर कहा कि जनता को गुमराह करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में लगातार नई परियोजनाएं शुरू हो रही हैं। रनौत ने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को कथित एलपीजी संकट से उसी तरह बाहर निकलने वाले हैं, जैसे उन्होंने कोविड महामारी के दौरान देश का नेतृत्व किया था। मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि एलपीजी की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार ने पूर्ण आश्वासन दिया है, लेकिन विपक्ष दहशत फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी भारत लगातार प्रगति कर रहा है। वहीं दूसरी ओर, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा। विपक्ष का आरोप है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण देश में एलपीजी की कमी की स्थिति पैदा हो रही है और इस पर संसद में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।

## घरेलू फ्लाइटों पर एयर इंडिया ने 399 रुपये सरचार्ज की बढ़ोतरी की

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर ईरान-इस्राइल युद्ध का असर दिख रहा है। अब उड़ानें महंगी हो गई हैं। घरेलू फ्लाइटों पर एयर इंडिया ने 399 रुपये सरचार्ज की बढ़ोतरी कर दी है। बढ़ा हुआ सरचार्ज आज यानी गुरुवार से लागू हो गया है। अन्य एयरलाइंस की ओर से इस लेकर तैयारियां चल रही हैं। सरचार्ज बढ़ोत्तरी के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर 1200 रुपये तक अधिक चुकाना पड़ सकता है। खाड़ी संकट ने लोगों के जीवन पर अब खासा असर डालना शुरू किया है। दरअसल, ईरान पर अमेरिका और इस्राइल के हमले और पलटवार ने खाड़ी देशों में तनाव को भड़का दिया है। इस युद्ध के कारण तेल-गैस को लेकर देश में पैनिक जैसी स्थिति है। वहीं, अब एयर ट्रैवल भी महंगा होता जा रहा है। इराक का एयरस्पेस पूरी तरह बंद किए जाने से अमेरिका यूरोप की कनेक्टिंग फ्लाइट के भी काफी महंगी होने के आसार हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर तैनात एक एयरलाइंस के अधिकारी के अनुसार, युद्ध के बाद भी इराक के एक सिरे से होते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स जा रही थीं।

# गुजरात आ रहे जहाज पर ईरानी हमलों के बाद भड़का भारत कहा- अब ऐसी घटनाएं न हों

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** होर्मुज जलडमरूमध्य में थाईलैंड के एक मालवाहक जहाज पर हुए हमले के बाद भारत ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पश्चिम एशिया में वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की बढ़ती घटनाओं पर भारत ने गहरी चिंता जताते हुए इन हमलों को तुरंत रोकने की मांग की है। यह विवाद तब गहराया जब गुजरात के कांडला बंदरगाह की ओर आ रहे एक जहाज मयूरी नारी पर ईरानी सेना के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) द्वारा हमला किए जाने की खबर आई।

विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि भारत वाणिज्यिक जहाजों को सैन्य संघर्ष का हिस्सा बनाने की कड़ी निंदा करता है। मंत्रालय के अनुसार, 11 मार्च को होर्मुज जलडमरूमध्य में थाई जहाज मयूरी नारी पर हमला हुआ, जो भारत के कांडला आ रहा था। अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों पर नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा स्वीकार्य नहीं है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि इन संघर्षों में अब तक

कई भारतीय नागरिकों सहित कई निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। हमलों की बढ़ती तीव्रता और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भारत ने स्पष्ट किया कि निर्दोष नागरिकों को खतरे में डालना अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है।

रिपोर्ट के अनुसार, बुधवार को ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य में तीन जहाजों पर गोले दागे गए। थाईलैंड के ध्वज वाले जहाज मयूरी नारी ने बुधवार सुबह संयुक्त अरब अमीरात के खलीफा बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की थी। सुबह करीब 11 बजे इस पर हमला हुआ। रॉयल थाई नेवी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक दल के 20 सदस्यों को बचाकर ओमान पहुँचाया है, जबकि तीन अन्य सदस्यों की तलाश अभी भी जारी है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा है, जहाँ से वैश्विक कच्चे तेल की 20 प्रतिशत आपूर्ति होती है। इन हमलों के कारण यह मार्ग बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है, जिससे वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति और कीमतों पर असर पड़ सकता है। इस बीच, भारत सरकार ने खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लगभग एक करोड़ भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पुष्टि की कि हालिया संकट के दौरान एक पोत पर हुए हमले में दो भारतीयों की मौत हुई है और एक लापता है। वर्तमान में ईरान में लगभग 9,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनके साथ भारतीय दूतावास लगातार संपर्क में है। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस क्षेत्र के विभिन्न देशों के नेताओं और अपने समकक्षों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके।

## महाराष्ट्र में विधान भवन को बम से उड़ाने की धमकी, मीडिया को नहीं जाने दिया अंदर

**-गहन तलाशी के बाद झूठी निकली धमकी, ईमेल भेजने वाली की तलाश शुरु**

मुंबई (एजेंसी)। महाराष्ट्र राज्य विधानसभा परिसर, विधान भवन को उड़ाने की धमकी देने वाले ईमेल के बाद गुरुवार को सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, जिसके चलते बजट सत्र के दौरान जांच शुरू होने तक मीडियाकर्मियों और आम जनता को अंदर नहीं जाने दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को अधिकारियों को एक चिंताजनक ईमेल मिला, जिसमें दक्षिण मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित विधान भवन में बम विस्फोट की स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। राज्य विधानसभा और विधान परिषद में गरमागरम राजनीतिक बहसों के बीच बजट पर सक्रिय रूप से विचार-विमर्श चल रहा था। अंदर मौजूद विधायक कड़ी निगरानी में कार्यवाही जारी रखे रहे, शुरुआत में उन्हें बाहरी अराजकता की जानकारी नहीं थी, क्योंकि इस खतरे ने महाराष्ट्र की विधायी संस्था के केंद्र में स्थित इस प्रतिष्ठित भवन में सामान्य आवागमन को बाधित कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक विधान भवन में बम निरोधक दस्ते ने गहन तलाशी के बाद परिसर को सुरक्षित घोषित कर दिया और धमकी को झूठी बताया। अब धमकी भरा ईमेल भेजने वाले व्यक्ति को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। सदन की कार्यवाही सुबह 11:00 बजे फिर शुरू हुई, जिससे बजट सत्र बिना किसी देरी के जारी रहा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पंकज भोइर ने खुलासा किया कि गुरुवार सुबह 6:27 बजे विधान भवन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और हाईकोर्ट को निशाना बनाते हुए बम विस्फोट की चेतावनी वाला एक धमकी भरा ईमेल मिला था। जांच से पता चलता है कि ईमेल फर्जी था।

## आंध्र प्रदेश के घरों में खौल रही सफेद मौत, मिलावटी दूध से अब तक 12 की गई जान

**-इस घटना ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया, दूध विक्रेता हिरासत में जांच शुरु**

**गोदावरी (एजेंसी)।** आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अस्पताल के वार्डों में तड़पते बुजुर्ग, पेशाब रुकने से फूलते शरीर और उल्टियों के बीच अपनी आखिरी सांसें गिनते मासूमों ने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया है। यह सब बुरे सपने से कम नहीं है। जहां सुबह की चाय और बच्चों का दूध धीमा जहर बनकर घरों में दाखिल हुआ। वरलक्ष्मी मिल्क डेरी से निकले उस मिलावटी दूध ने देखते ही देखते 12 घरों के चिराग बुझा दिए। यह महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि नृशंस सामूहिक हत्या जैसा है, जहां मुनाफे के लालच में दूध में घातक रसायन मिलाया गया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस खौफनाक कांड ने साबित कर दिया है कि हमारी खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आज 12 मौतें हुई हैं, लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त कितने और घरों में यह सफेद मौत घूम रही है? पूरा इलाका श्मशान जैसी शांति और गहरे तनाव की चपेट में है, जहां हर दरवाजा खटखटाने वाला दूधवाला अब एक कातिल नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस समूह की पहचान सबसे पहले 22 फरवरी को हुई थी, जब कई बुजुर्ग व्यक्तियों को पेशाब न आना, उल्टी, पेट दर्द और अन्य दिक्कतों के चलते अस्पतालों में भर्ती कराया गया था।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि कई विभागों में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नैदानिक ??जांच में रक्त में यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया, जो विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आने का संकेत देता है। शुरूआती जांच से पता चला है कि कोरुकोंडा मंडल के नरसपुरम गांव में स्थित वरलक्ष्मी मिल्क डेरी से 106 परिवारों को आपूर्ति किया जाने वाला दूध इसका स्रोत हो सकता है। आपूर्ति तुरंत रोक दी गई है। इलाके में आपातकालीन चिकित्सा शिविर स्थापित किये गए हैं और चिकित्सकों और विशेषज्ञों का एक दल तैनात किया गया है। डेरी से आवश्यक नमूने लिए गए हैं और संदिग्ध दूध विक्रेता अड्डाला गणेश्वरराव (33) को हिरासत में लिया है। डेरी को सील कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

# जनसंख्या दर में भारी गिरावट के कारण जापान से भी ज्यादा बुरे हालात में सिक्किम

### भारत की जनसंख्या 2050 तक तेजी से बूढ़ी होगी

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** देश कम फर्टिलिटी दर को लेकर परेशान है। इसका बड़ा कारण है कि भारत की जनसंख्या 2050 तक तेजी से बूढ़ी होगी। तब 60 साल से अधिक उम्र वालों की तादाद कुल जनसंख्या का लगभग 20 प्रतिशत होगा है। आजादी के 100वें साल तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती सिक्किम में है। वहां जापान से भी बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। सरकार करीब 4 बरस से प्रयास कर रही है, पर हालात नहीं सुधर रहे। देश की कुल जन्म दर (टीएफआर) 2.1 के स्थिर स्तर के मुकाबले 1.9-2.0 के बीच है, जबकि सिक्किम में यह बेहद निचले स्तर 1.1 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि औसतन हर महिला 1.1 बच्चे को जन्म दे रही है। 2005-06 में यह 2.0 थी, 2015-16 में 1.2 और 2025-26 में 1.1 तक आ गई। इस गिरावट के चलते सिक्किम का हाल जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से भी गंभीर हो गया है। अब सरकार नैशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ साझेदारी कर यह समझने की कोशिश कर रही है कि फर्टिलिटी क्यों कम हो रही है। सिक्किम जैसी स्थिति दुनिया के कई देशों की है। इसके बाद सिक्किम सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए हैं। 2022 में शुरू की गई वात्सल्य योजना के तहत बांझपन जैसी समस्याओं से जूझ रहे

दंपतियों को आईवीएफ जैसे महंगे उपचार के लिए 3 लाख रुपये की मदद दी गई। योजना शुरू होने के बाद 38 महिलाओं ने पंजीकरण कराया, जिससे स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य कारण भी टीआरएफ घटने में योगदान दे रहे हैं।

इतना ही नहीं सिकिम्म सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन नीति भी लागू की गई। दूसरे बच्चे पर वेतन वृद्धि, तीसरे बच्चे पर अतिरिक्त वेतन, महिला कर्मचारियों के लिए एक साल की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को पैटरनिटी लीव दी गई। बच्चों की देखभाल के लिए अटेंडेंट की व्यवस्था की गई। निजी क्षेत्र में भी महिलाओं को दूसरे बच्चे पर 5,000 रुपये और तीसरे बच्चे पर 10,000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

विश्व स्तर पर भी जन्म दर बढ़ाने की चुनौतियां आम हैं। सिंगापुर में टीआरएफ 1.0 के आसपास है, जबकि दक्षिण कोरिया में यह 0.7 तक गिर गई। इन देशों में लंबे समय से बेबी बोनस, टैक्स रिबेट, सस्ती चाइल्ड केयर और हाउसिंग इंसेंटिव जैसी नीतियां लागू हैं, लेकिन परिणाम सीमित रहे हैं। हंगरी को थोड़ी सफलता मिली है, जहां 2011 में टीआरएफ 1.23 था और सरकार ने हाउसिंग सब्सिडी, कम ब्याज पर कर्ज और चार या अधिक बच्चों वाली महिलाओं के लिए आयकर छूट जैसी नीतियां लागू कीं। 10 साल बाद टीआरएफ 1.5 तक बढ़ा, लेकिन यह भी रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। जनसंख्या संतुलन बनाए रखने और बूढ़ी आबादी के बढ़ते बोझ को संभालने के लिए जन्मदर बढ़ाने के प्रयासों को और प्रभावी, समग्र और दीर्घकालिक रणनीतियों के साथ लागू करना होगा। इसके लिए स्वास्थ्य, वित्तीय प्रोत्साहन और सामाजिक समर्थन सभी आवश्यक हैं।

## फारूक अब्दुल्ला पर हमला: सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचा था हमलावर, 20 साल से बना रहा था योजना

**जम्मू (एजेंसी)।** जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला बुधवार को एक भीषण हमले में बाल-बाल बच गए। जम्मू के बाहरी इलाके ग्रेटर कैलाश स्थित होटल रॉयल पार्क में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान एक सशस्त्र हमलावर ने उन पर बेहद करीब से निशाना साधने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की त्वरित कार्रवाई और मुस्तैदी के कारण एक बड़ी अनहोनी टल गई, लेकिन इस दौरान हमलावर की बंदूक से एक राउंड फायरिंग भी हुई जिससे समारोह में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस ने हमलावर की पहचान 63 वर्षीय कमल सिंह जमवाल के रूप में की है, जो जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का निवासी है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने सुरक्षा एजेंसियों के सामने जो खुलासे किए, वे चौंकाने वाले हैं। जमवाल ने दावा किया कि वह पिछले दो दशकों से फारूक अब्दुल्ला की हत्या की योजना बना रहा था और इसे अपना व्यक्तिगत एजेंडा बताया। आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्तौल बरामद हुई है, जिसे उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक बताया है। अधिकारियों के अनुसार, घटना के समय आरोपी नशे में धुत था और उसने खुद को एक अज्ञात जागरण मंच का अध्यक्ष भी बताया है। यह सनसनीखेज घटना

उस समय हुई जब फारूक अब्दुल्ला और केंद्र शासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी एक पार्टी नेता के बेटे के विवाह समारोह से वापस लौट रहे थे। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि हमलावर पीछे से डॉ. अब्दुल्ला के बिल्कुल करीब पहुंच गया और उन पर बंदूक तान दी। इससे पहले कि वह घातक वार कर पाता, अब्दुल्ला की जेड प्लस सुरक्षा में तैनात क्लोज प्रोटेक्शन टीम ने फुर्ती दिखाते हुए उसे दबोच लिया। इस दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने आरोपी की जमकर धुनाई भी की। इस घटना ने जम्मू-कश्मीर में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस चूक पर गहरा दुख और आश्चर्य व्यक्त किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर एक व्यक्ति जेड प्लस सुरक्षा वाले पूर्व मुख्यमंत्री के इतने करीब लोडेड पिस्तौल के साथ कैसे पहुंच गया? वहीं, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने भी इसे सुरक्षा में भारी लापरवाही करार देते हुए कहा कि जब पूर्व सीएम, डिप्टी सीएम और सलाहकार एक ही स्थान पर मौजूद हों, तो ऐसी घटना सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलती है। फिलहाल जम्मू पुलिस ने मामला दर्ज कर विस्तृत जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने अभी तक किसी आतंकी संलिप्तता से इनकार किया है, लेकिन इस बात की गहराई से तफ्तीश की जा रही है कि आरोपी हथियार के साथ सुरक्षा घेरे को भेदकर अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब रहा।

## मोनालिसा और फरमान खान की शादी पर विवाद शुरु, पति ने हर एक सवाल का दिया जवाब

**मुंबई (एजेंसी)।** प्रयागराज महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए अपनी सादगी और खूबसूरती से रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनीं मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी कजरारी आंखों और मुस्कान से लाखों प्रशंसकों का दिल जीतने वाली मोनालिसा ने अपने करियर की औपचारिक शुरुआत से पहले ही वैवाहिक जीवन में कदम रख दिया है। बुधवार को उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड और सह-अभिनेता फरमान खान के साथ शादी रचाई।

अपनी प्रेम कहानी का खुलासा करते हुए फरमान ने बताया कि वे दोनों एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे, जहां से उनकी बातचीत शुरू हुई। फरमान के अनुसार, मोनालिसा ने ही उन्हें पहले प्रपोज किया था। उन्होंने कहा, हमारा प्यार महज 6 महीने पुराना है, लेकिन यह जुड़ाव 60 साल के बराबर महसूस होता है, इसलिए हमने साथ रहने का फैसला किया। शादी के बाद मोनालिसा ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि उन्हें केरल और वहां के लोग बहुत पसंद आए हैं। फरमान ने यह भी संकेत दिया कि यदि

मोनालिसा को यहां का वातावरण रास आता है, तो वे केरल में ही बसने पर विचार कर सकते हैं। फिलहाल इस नवविवाहित जोड़े ने केरल के स्थानीय लोगों और पुलिस प्रशासन को उनके कठिन समय में सहयोग करने के लिए शुक्रिया अदा किया है।

चूंकि फरमान मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं, इसलिए मोनालिसा के माता-पिता इस अंतरधार्मिक रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। हालांकि, अपने प्यार को मुकम्मल करने के लिए मोनालिसा ने परिवार से बगावत का रास्ता चुना और घर छोड़कर शादी करने का फैसला किया। मोनालिसा और फरमान ने कानून का सहारा लेते हुए पहले केरल में सिविल मैरिज की और फिर तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध अरुमनूर नैनार मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज के साथ विवाह बंधन में बंधे। इस दौरान पुलिस सुरक्षा के बीच फरमान ने मोनालिसा की मांग में सिंदूर भरा। इंटरनेट पर वायरल हो रही तस्वीरों में मोनालिसा लाल साड़ी, गले में वरमाला और मांग में सिंदूर लगाए बेहद खुश नजर आ रही हैं। इस शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक विवाद भी खड़ा हो गया, जिसमें दावा किया गया कि मोनालिसा अभी नाबालिग हैं। इन खबरों पर लगाम लगाते हुए उनके पति फरमान खान ने सार्वजनिक रूप से मैरिज सर्टिफिकेट और आधार कार्ड दिखाते हुए स्पष्ट किया कि मोनालिसा 18 वर्ष से अधिक की हैं और पूरी तरह वयस्क हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि गलत खबरें फैलाई जा रही हैं कि वह मैच्योर नहीं हैं, जबकि कानूनी दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि इसका प्रमाण है।

# बिहार चुनाव में बीजेपी के बटुए से निकले 146.71 करोड़... जीते सबसे ज्यादा 89 विधायक

**-कांग्रेस ने 35.07 करोड़ रुपये खर्च किए, जीते सिर्फ 6 विधायक**

**नई दिल्ली (एजेंसी)।** बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतने के लिए बीजेपी ने सभी पार्टियों से ज्यादा खर्च किया है। बीजेपी ने 146.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वहीं कांग्रेस ने कुल 35.07 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। बीजेपी ने जमा पूंजी का 2 फीसदी खर्च किया, जबकि कांग्रेस ने अपनी कुल जमा पूंजी का 28 फीसदी पैसा खर्च किया है। बीजेपी ने बीते बिहार विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार ज्यादा पैसा खर्च किया। 2020 में बीजेपी ने करीब 54 करोड़ खर्च किए थे, लेकिन इस बार 146.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

बिहार में बीजेपी को पैसा खर्च करने का फल भी मिला। राज्य में 89 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, दूसरी ओर कांग्रेस ने बीजेपी की तुलना में भले ही पैसा कम खर्च किया हो, लेकिन अपनी जमा पूंजी का बहुत बड़ा हिस्सा बिहार में खर्च किया।

चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अपने खर्च की हिसाब देती हैं। इसके तहत बिहार चुनाव में खर्च किए पैसे का लेखा-जोखा सियासी दलों ने चुनाव आयोग को दिया हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने बिहार चुनाव खर्च की रिपोर्ट 10 फरवरी को चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसमें पार्टी ने बताया है कि उसने 146.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। वहीं, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 35 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, तब सीपीआई (एम) ने महज 26.75 लाख रुपये खर्च किए हैं। बहुजन समाज पार्टी ने बिहार चुनाव में सिर्फ 9.01 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आरजेडी और जेडीयू सहित दूसरे दलों के खर्च का लेखा-जोखा अभी चुनाव आयोग को उपलब्ध नहीं कराया हैं।

बीजेपी ने चुनाव प्रचार के विज्ञापन पर खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा गूगल इंडिया लिमिटेड पर किया, जिसे पार्टी ने 14.27 करोड़ रुपये दिए। इसके अलावा बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों पर 29.71 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जिसमें पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर दिया है। कांग्रेस ने बिहार चुनाव में खर्च किए गए 35 करोड़ रुपये में से 12.83 करोड़ रुपये स्टार कैंपेनर्स की यात्रा पर दिए। इसके अलावा कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपने के लिए 11.24 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बिहार में निकाली गई वोटर अधिकार यात्रा पर भी खर्च किए।

रिपोर्ट से पता चलता है कि बीते साल नवंबर में बिहार चुनाव खत्म होने पर बीजेपी का क्लोजिंग बैलेंस 7,088.58 करोड़ रुपये था। इसके मुताबिक चुनाव से पूर्व बीजेपी के पास 7235.26 करोड़ रुपये था, जिसमें से 146.71 करोड़ खर्च किया। इसके बाद 7,088.58 करोड़ रुपये बचे थे। इस तरह बीजेपी ने अपनी जमापूंजी का करीब 2 फीसदी पैसा ही बिहार चुनाव में खर्च किया है। वहीं, कांग्रेस के पास बिहार चुनाव के बाद कुल 89.13 करोड़ रुपये बचे थे। कांग्रेस ने चुनाव में 35.07 करोड़

रुपये खर्च किए हैं। इस लिहाज से कांग्रेस के चुनाव से पहले 124.2 करोड़ रुपये था, जिसमें से 35.07 करोड़ रुपये खर्च करने का मतलब साफ है कि पार्टी ने अपनी जमापूंजी का 28.23 फीसदी पैसा बिहार चुनाव में खर्च किया।

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 89 विधायक जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली हैं। बिहार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के द्वारा खर्च किए गए पैसे को विधायकों की संख्या के लिहाज से बीजेपी को एक विधायक 1 करोड़ 64 लाख का पड़ा। वहीं कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक जीते हैं, इसके बाद कांग्रेस को एक विधायक 5 करोड़ 83 लाख का पड़ा।